नई दिल्ली
23 जून, 2026 मंगलवार
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 83

अनोखे अंदाज़ और निराले टेवर के साथ इन्साफ की डगर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

RNI No. DELMUL/2012/47011

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

मनिका ने एशियाई खेलों के लिए चयन की प्रक्रिया पर उठाए सवाल 07

संक्षिप्त वार्ता

दो घंटे में तय होगा दिल्ली से लखनऊ का सफर, मिली मंजूरी

नई दिल्ली। देश को अगले साल के मध्य में पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस बुलेट ट्रेन के लिए काम कई सालों से जारी है। इस बीच देश के सात नए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत दिल्ली से वाराणसी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, जिसमें बुलेट ट्रेन महज दो घंटे में ही दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देगी। वहीं, दिल्ली से वाराणसी के लिए महज तीन घंटे 15 मिनट का ही समय लेगा। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और यह हवा से बातें करेगी।

नीट मामले को लेकर सीजेपी का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी

नई दिल्ली। नीट मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों ने कैंडल मार्च की अपील करते हुए किसान संगठनों से भी आंदोलन में शामिल होने का आव्हान किया है।

जंतर-मंतर में मौजूद प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने नीट परीक्षा विवाद और कथित तौर पर इससे प्रभावित होकर आत्महत्या करने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए सोमवार शाम 5:30 बजे जंतर-मंतर पर कैंडल मार्च आयोजित करने की अपील की।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को ग्वालियर विमानतल पर दी भावभीनी विदाई

भोपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मध्यप्रदेश के 5 दिवसीयभ्रमण के बाद22 जून को सुबह वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुईं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु श्योपुर जिले के कूनों से हैलीकॉप्टर से वायुसेना के विमानतल महाराजपुरा ग्वालियर पधारीं। उनके साथ मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल भी थे। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल श्री पटेल, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह एवं महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार ने विदाई दी। विमानतल पर अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, डीजी होमगार्ड सुश्री प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव, संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री, आईजी श्री अरविंद कुमार सक्सेना, डीआईजी श्री असित यादव, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय एवं वायु सेना के अधिकारी उपस्थित रहे।

'नीचे आग...ऊपर मौत का धुआं'

किसी ने खुद को बाथरूम में बंद किया तो कोई खिड़की से कूदा

लखनऊ कोचिंग संस्थान अग्निकांड में 15 की मौत, घटनास्थल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, 22 जून (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार को एक कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर तत्काल लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ घायलों का हालचाल जाना।

जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अलीगंज स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। इमारत के निचले हिस्से में पालतू पशुओं की दुकान और क्लीनिक संचालित था, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कोचिंग और एनिमेशन प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घना धुआं पूरी इमारत में फैल गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य में 14 दमकल वाहनों के साथ हाइड्रोलिक सीढ़ियों का भी उपयोग किया गया। घने धुएं के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण हो गया, जिसके चलते अग्निशमन कर्मियों को बगल की इमारत की दीवार तोड़कर भीतर प्रवेश करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग से बचने के लिए कुछ विद्यार्थियों ने इमारत से छलांग भी लगाई। घायलों को तत्काल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुई हैं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हुई है और कई घायलों का उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घटना की गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और अपर प्रमुख सचिव गृह को स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम मोदी ने जताया दुख

हादसे में पीएम मोदी ने दुख जताया है. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एक्स पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग की घटना में हुई मौतों से दुखी हूं. शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं.

नेताओं ने व्यक्त किया गहरा शोक

हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती तथा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, जबकि अखिलेश यादव ने घटना की निष्पक्ष जांच कर भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। फिलहाल पुलिस, प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीमें पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है और अब इमारत में कोई भी व्यक्ति फंसा नहीं है।

मजदूरों से भरी पिकअप से भिड़ंत में उजड़ गए कई घर

भीषण हादसा : मौत बनकर दौड़ा ट्रक

छिंदवाड़ा-बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह टेमनी खुर्द के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। रोजी-रोटी की तलाश में खेतों की ओर जा रहे मजदूरों की पिकअप वाहन अचानक मौत के सफर में बदल गई, जब सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर ही कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

छिंदवाड़ा/जबलपुर

5 मजदूरों की मौके पर मौत, 20 से अधिक घायल

प्रशासन ने देर शाम तक मृतकों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे तेज रफ्तार ट्रक का टायर अचानक फट गया। इसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर मजदूरों से भरी पिकअप से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग कई मीटर दूर तक जा गिरे। कुछ लोग सड़क पर तो कुछ आसपास के खेतों में जा गिरे। हादसे के बाद घटनास्थल का दृश्य बेहद दर्दनाक था। सड़क पर खून बिखरा पड़ा था और कई शव क्षत-विक्षत अवस्था में मिले।

सीएम ने की आर्थिक सहायता देने की घोषणा

घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतक परिजनों को ४-४ लाख रूपए देने व अति गंभीर मरीजों को १-१ लाख रूपए देने, वहीं घायलों को ५० हजार रूपए देने की घोषणा की है।

खेतों में काम करने जा रहे थे मजदूर

जानकारी के अनुसार पिकअप में सवार 25 से 30 मजदूर जिले के मछेरा गांव के निवासी थे, जो खेतों में काम करने जा रहे थे। टक्कर के बाद ट्रक सड़क किनारे पेड़ों को तोड़ता हुआ खेत में उतर गया, जबकि पिकअप भी सैकड़ों मीटर दूर खेतों में जा घुसी। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकालने में मदद की। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

पूर्व सांसद व विधायक ने जताया शोक

इस दर्दनाक दुर्घटना पर पूर्व सांसद नकुलनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पांढुर्ना विधायक नीलेश ऊइके भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और प्रशासन को उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

भीषण सड़क हादसे में बब्बू पिता भूरूराज बेटे ४० वर्ष निवासी मछेरा, सावित्री पति सुरेश सिंग बनके ३१ वर्ष निवासी मछेरा, शिवकली पिता शिवपाल धुर्वे ३५ वर्ष, लीलावती पति गरीबशीलू ५५ वर्ष सहित संतोष पिता केशवराव सावनेरे निवासी हथलेवा टोला की मौके पर मौत हो गई। वहीं २० से २५ लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है।

भारत में एक ऐसी जगह जहां भारतीयों की एंट्री नहीं, जाने के लिए अनुमति जरुरी

नई दिल्ली। भारत के बाहर तो ठीक देश के अंदर ही एक ऐसी जगह है, जहां भारतीयों को सीधे एंट्री नहीं है? यह मजाक नहीं हैं सच है। आज भी भारत की सरजमीं पर एक ऐसा इलाका है जहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट जैसी अनुमति या स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। यह इलाका है पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित तीन बीघा कॉरिडोर और दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव, जो भारत में है, लेकिन यहां की व्यवस्था बांग्लादेश के नियंत्रण में है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन बीघा कॉरिडोर मात्र 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है। 1996 में भारत सरकार ने इसे बांग्लादेश को 999 साल के लिए लीज पर दे दिया था ताकि बांग्लादेश के दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव के रहने वाले मुख्य भूमि तक पहुंच सकें। 2015 के भारत-बांग्लादेश एन्क्लेव समझौते के बाद 100+ एन्क्लेव खत्म हो गए, लेकिन दहाग्राम अभी भी खास स्थिति में है।

इस जगह पर भारतीयों को एंट्री के लिए स्पेशल परमिट या स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होती है, लेकिन बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी दिक्कत के कॉरिडोर से आ-जा सकते हैं। इस इलाके में बांग्लादेशी झंडे, बांग्लादेशी मुद्रा, स्कूल, अस्पताल और कानून व्यवस्था बांग्लादेशी तरीके से चलती है। यहां भारतीय सुरक्षा बल चेकिंग करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन बांग्लादेश के अधीन है। इस एन्क्लेव में करीब 20 हजार बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। यहां की जिंदगी, भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह बांग्लादेश से जुड़ी है।

भारतीय इलाकों से अलग हो जाती है

रिपोर्ट के मुताबिक लोग बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेश सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। यह इलाका भारत-बांग्लादेश सीमा की संवेदनशीलता के कारण सुरक्षा दृष्टि से अहम है। बिना अनुमति के जाने पर बीएसएफ रोक सकती है। पर्यटकों और आम भारतीयों को पहले से परमिट लेना या स्थानीय प्रशासन से अनुमति मांगनी पड़ती है। इससे यह जगह भारत में होते हुए भी भारतीय इलाकों से अलग हो जाती है।

200 किलो चांदी की ईंटों पर विवाद : सिंधी समाज को 5 साल बाद भी नहीं मिली रसीद

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक नए विवाद के केंद्र में आ गया है। इस बार सिंधी समाज ने मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि उन्हें आज तक इन दान की गई ईंटों की कोई रसीद या आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजू मनवानी के अनुसार, 26 जनवरी 2021 को दुनिया भर के सिंधी समाज के सहयोग से ये चांदी की ईंटें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को कारसेवक पुरम में सौंपी गई थीं। इन ईंटों पर समाज के पूजनीय देवता झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी और इस कार्यक्रम में 12 विभिन्न देशों के सिंधी प्रतिनिधि उपस्थित थे। डॉ. मनवानी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि चांदी की जांच के बाद उन्हें दान की रसीद प्रदान की जाएगी, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ।

डॉ. मनवानी का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावे और निर्माण कार्यों में कथित हेराफेरी को लेकर चल रही हालिया खबरों के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब सिंधी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से महिपाल जैसे पूर्व कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने चढ़ावे की रकम में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और निर्माण कार्य में व्यापक घोटाले के आरोप लगाए हैं।

इसी तरह, रोकडिया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा ने भी दावा किया है कि उनके जौनपुर के शिष्य अजय विश्वकर्मा द्वारा दान किए गए रामलला के लिए सुंदर हार और चरण पादुका की रसीद एक साल बाद भी ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

...आरोपों की तह तक जाने का प्रयाा करेगी

इन संगीन आरोपों के बाद, मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसआईटी ने पहले चरण की जांच में कुछ शुरूआती पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है और अब दूसरे चरण में उन सभी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ट्रस्ट पर विभिन्न आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य उनके दावों की सत्यता का पता लगाना है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। महिपाल, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए थे, बाद में किसी चैनल या मंच पर नजर नहीं आए और उन्होंने लोगों के फोन उठाना भी बंद कर दिया। एसआईटी की जांच अब इन्हीं जैसे आरोपों की तह तक जाने का प्रयास करेगी।

संपादकीय

राम नाम की लूट है...

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा-चोरी के संदर्भ में अब यह अहम सवाल है कि ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट के सदस्यों और उनके पालतू चंपुओं पर सिर्फ चढ़ावे की चोरी-डकैती के ही आरोप नहीं हैं, बल्कि भगवान राम को पहनाए गए, हीरे-जवाहरात के हार, चांदी की चरण-पादुका, अन्य गहने-आभूषण गायब करने के भी संवेदनशील आरोप हैं। फिर आरोपित राम मंदिर के ट्रस्ट में क्यों हैं? ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पर राम मंदिर में ही इंजीनियर रहे दीनानाथ वर्मा के भ्रष्ट आरोप हैं कि वह निर्माण-कार्यों में 40 फीसदी कमीशन मांगते थे। फर्जी बिल बना कर निर्माण-कार्यों में मोटा घोटाला किया गया है। हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन कीचड़ तो उछला है! सबसे अधिक आपत्तिजनक और अवैध यह माना जा रहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल ने नजूल की जमीन कैसे और क्यों खरीदी? एक उदाहरण सामने आया है कि 2.92 करोड़ रुपए की नजूल-भूमि 23-24 करोड़ रुपए में क्यों खरीदी गई? नजूल की जमीन सरकारी संपत्ति होती है, जो राज्य सरकार को सौंपी जाती है। यह जमीन लीज, पट्टे पर तो दी जा सकती है, लेकिन इसे बेचा-खरीदा नहीं जा सकता। जमीन से जुड़ी ऐसी भ्रष्ट विसगतियों के आरोप तब से लगाए जा रहे हैं, जब राम मंदिर का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था। अभी दो-तीन दिन पहले उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के प्रवास पर थे, लेकिन ट्रस्ट को स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि चंपत राय और अन्य आरोपितों, संदिग्धों को उनसे दूर रखा जाए। आखिर क्यों? क्या विशेष जांच टीम ने मुख्यमंत्री को कुछ विस्फोटक खुलासे किए हैं? चंपत राय समेत अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सुभाष श्रीवास्तव आदि पर संगीन आरोप हैं और सभी आरएसएस के पदाधिकारी रह चुके हैं। क्या सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए खामोश हैं?

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके एवं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने टीवी चैनलों के साक्षात्कारों में चढ़ावा-चोरी को डाका करार दिया है और नजूल की जमीन खरीदने पर सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद चंपत राय की चारित्रिक निष्ठाएं गाई जा रही हैं कि वह पूजा की थाली का चावल तक चुरा नहीं सकते। फकत-फकीर और संत किस्म के व्यक्ति हैं। सवाल है कि जिस मंदिर में करोड़ों रुपए का दान आता हो, करोड़ों रुपए निर्माण और व्यवस्था पर खर्च किए जाते रहे हों, क्या उसके प्रशासन का दायित्व किसी संत-फकीर को सौंपा जा सकता है? क्या ट्रस्ट भी दैवीय है अथवा ट्रस्ट के सदस्य या संबद्ध लोग खास राम-भक्त हैं? सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर, प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह ट्रस्ट गठित किया था। ऐसे क्या सुर्खाव के पर लगे हैं, जो इसे खंडित नहीं किया जा सकता? वैसे अब चर्चा सुनी जा रही है कि एक हालिया सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनाया जा सकता है, लिहाजा कुछ चेहरों पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल हमारी अगाध आस्था है कि प्रभु राम देश की आत्मा हैं, प्राण हैं, जिंदगी हैं, मन-विचार हैं, प्रार्थना हैं और असीमित मयार्दा हैं। करोड़ों राम-भक्तों की ऐसी आस्थाओं, भक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता। यह धारणा पैदा नहीं की जा सकती कि राम मंदिर भी लूट, चोरी-चकारी का अड्डा है। राम के प्रति जरा-सा भी मोहभंग यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई राम-नामकी लूट नहीं मची है कि कोई भी लूट ले! सवाल यह भी बेहद गंभीर है कि राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और अखाड़ों के महामंडलेश्वर संतों को क्यों नहीं रखा गया? संघ परिवार का ही ट्रस्ट क्यों बना दिया गया? प्रधानमंत्री मोदी तो परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। बहरहाल आरोप तो आंदोलन के दौरान असंख्य राम-शिलाओं को लेकर भी सामने आए हैं। उनमें चांदी की शिलाएं भी थीं। यह चोरी-डकैती तिरुपति मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, शिरड़ी के साईं बाबा मंदिर आदि में भी होती रही है। करोड़ों की हेरा-फेरी, डकैती सामने आती रही है, लेकिन वक्त बीतने के साथ-साथ सब कुछ दब-ढक जाता है। क्या इस मामले में उचित कार्रवाई होगी?

टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देती सरकार

यकीनन इस समय सरकार देश के 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले और करीब 174 अरब डॉलर के बाजार आकार के टेक्सटाइल्स सेक्टर को मजबूती देने के लिए रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ रही है। सरकार ने एक जून से पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हो रहे टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आगामी पांच माह के लिए कपास आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से माफ कर दिया है। सरकार लगातार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है। हाल ही में लागू किए गए नए श्रम कानूनों से टेक्सटाइल सेक्टर को जोरदार बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के विकास के लिए पीएम मित्र पार्क मील का पत्थर हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रावधानों का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। साथ ही पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में सुधार के लिए उठाए गए बहुआयामी कदम टेक्सटाइल सेक्टर को लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस परिदृश्य के मद्देनजर वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की रेटिंग बढ़ाई है। इनवेस्टमेंट इनफॉरमेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का आउटलुक ह्यनेगेटिवह्न से बढ़ाकर ह्यस्टेबलह्न कर दिया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक जून से भारत और ओमान के बीच सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) लागू हुआ है। इस समझौते के तहत ओमान ने भारत के टेक्सटाइल सहित 99 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क पूरी तरह से शून्य कर दिया है।

इस शून्य शुल्क व्यवस्था के कारण, ओमान में भारतीय कपड़ों की लागत कम होगी, जिससे आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात में भारी उछाल आने की उम्मीद है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ओमान को लगभग 930 रुपए का टेक्सटाइल निर्यात किया था। यह पांच वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसी तरह एफटीए वाले अन्य देशों में जीरो या लगभग जीरो ड्यूटी एक्सेस की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रहे एफटीए से टेक्सटाइल निर्यात में भारी उछाल आया है। साथ ही आगामी महीनों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा यूरोपीय संघ के साथ एफटीए के क्रियान्वयन से इन देशों को भारत से तेजी से टेक्सटाइल निर्यात बढ़ेगा। खासतौर से यूरोप के 27 देशों के संगठन यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते पर अमल शुरू होने के दो-तीन वर्षों में ही यूरोपीय संघ को भारत से करीब 20 अरब डालर तक का

टेक्सटाइल निर्यात बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इन दिनों अमरीका के साथ जिस द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है, उसके तहत भारत को अमरीका में धागे और कपास से बने कपड़ों पर भारी शुल्क छूट हासिल होगी और टेक्सटाइल निर्यात ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत में टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देने के मद्देनजर पिछले माह 9 मई से पूरे देश में जमीनी स्तर पर लागू की गई चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन चार श्रम संहिताओं- मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता के तहत नए सरल श्रम कानून टेक्सटाइल उद्योग-कारोबार की मजबूती और विकास की नई संभावनाओं को आकार देने के मद्देनजर महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से व्यापार समझौतों का प्रभावी रूप से लाभप्रद क्रियान्वयन होगा। अब तय अवधि के लिए ठेके पर काम करने वाले कामगारों को स्थायी श्रमिकों के बराबर सभी लाभ मिलेंगे और वे 5 साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे।

नए श्रम नियम महिलाओं को रात की पाली में काम करने और देश भर में कर्मचारियों के राज्य बीमा लाभों का विस्तार करने की अनुमति भी देते हैं, इन सबसे श्रम की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ेगी और इसका बड़ा लाभ टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा। यह बात महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय ने सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने के लिए जो पीएम मित्र पार्क योजना शुरू की है, उसके तहत काम प्रगति पर है और उससे देश के टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊंचाई मिलेगी। पीएम मित्र पार्क प्रधानमंत्री के पांच-एफ विजन-फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्टरी, फैक्टरी से फैशन और फैशन से फॉरेन तक से प्रेरित है। यह एक ह्यआत्मनिर्भर भारतह्न के निर्माण की दृष्टि को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। सरकार की इस पहल से इन टेक्सटाइल पार्कों में करीब एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में एक अप्रैल से तेजी से क्रियान्वित हो रहे केंद्रीय बजट के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जिस तरह अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं, उससे भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वस्तुत: इन बजट प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र निर्माण का हब बनाना, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देना है। बजट में टेक्स-इको पहल वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित की गई है। ह्यटेक्स-इकोह्न पहल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। बजट में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए ह्यसामर्थ्य-2ह्न का अनावरण किया गया है। बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल भी महत्वपूर्ण है। यह पहल खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए, एक जिला एक उत्पाद को भी समर्थन देती है। बजट में निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार किया गया है। बजट के तहत तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो रक्षा, चिकित्सा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। नि:संदेह टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ऐसे अभूतपूर्व रणनीतिक प्रयासों से भारत का टेक्सटाइल उद्योग तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के तेजी से बढ़ने की संभावनाओं के बीच हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि विगत वर्षों में टेक्सटाइल सेक्टर पर अनिश्चितताओं और बदलावों का दबाव रहा है और अभी भी वर्ष 2026 में टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ते मौकों के बावजूद बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं, जिसमें लगातार लॉजिस्टिक्स पर असर डालने वाली जियोपॉलिटिकल रुकावटें, बढ़ती इनपुट और कम्प्लायंस लागत और सोर्सिंग जगहों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के साथ टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत दिखाई दे रही है। उम्मीद करें कि एक जून से 30 अक्टूबर तक कपास के आयात में सीमा शुल्क की छूट से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को पर्याप्त राहत मिलेगी और विदेशों में भारत के टेक्सटाइल निर्यातक प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। साथ ही विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के उत्पादों के लिए शुल्क मुक्ति पर प्रवेश की अनुकूलताएं, देश में हाल ही में लागू सरल श्रम कानून, पीएम मित्र पार्क तथा चालू वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को गति देने वाले प्रावधानों से टेक्सटाइल सेक्टर मजबूत होगा।

डा. जयंती लाल भंडारी, विख्यात अर्थशास्त्री

अपने दल से अलग क्यों जा रहे सांसद

राजनीति में अवसर की तलाश करना आज के राजनेताओं का प्रिय विषय बनता जा रहा है। सीधे शब्दों इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि राजनीति अब सेवा का मार्ग न होकर अवसरवादिता के आवरण को ओढ़ चुकी है। विपक्षी दलों खास कर तृणमूल कांग्रेस और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों का अलग होना कहीं न कहीं यही संकेत करता है कि ये सांसद अपने पार्टी के सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रखते थे, लिहाजा उन्होंने अपना खुद का एक राजनीतिक पाला बना लिया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि अब विपक्ष की संभावनाएं धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष की राजनीति का एक ही मुद्दा रह गया है, वह है आरोप की राजनीति। तुम आरोप लगाते रहो, हम काम करते जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ इसी प्रकार का खेल चल रहा है। यह बात सच है कि केवल आरोप लगाने की राजनीति के माध्यम से सत्ता का सिंहासन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित और जनहित की ओर जाना ही होगा। आज की राजनीतिक स्थिति का विचार किया जाए तो यह कहना उचित ही होगा कि भाजपा का प्रचार सत्ता पक्ष की ओर से कम विपक्ष की ओर से ज्यादा किया जा रहा है। आज विपक्ष के नेताओं के बयान बिना भाजपा के अधूरे ही रहते हैं।

राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि आज का राजनेता किसी न किसी हेतु के लिए ही राजनीति कर रहा है, ऐसे राजनेता की न तो किसी दल से वैचारिक समानता होती है और न ही किसी राजनीतिक नेतृत्व के प्रति निष्ठा ही रहती है। ऐसे राजनेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के अवसर की तलाश करते हैं। वर्तमान में विपक्षी राजनीतिक दलों के जो सांसद अपने दलों को छोड़ रहे हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं, वे अब शायद यह समझने लगे हैं कि उनका भविष्य अपने दल के साथ सुरक्षित नहीं है। इसका कारण यही है कि भारत की जनता को भारत के विकास की राजनीति पसंद आने लगी है। दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भाजपा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दल पूरा जोर लगाने के बाद भी पराजित होते जा रहे हैं। भविष्य में इनको सफलता मिलेगी, इसकी फिलहाल कोई गुंजाईश भी नहीं है।

वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग राह पर जा चुके हैं। इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक ताकत भी बेअसर हो गई है। और इसी कारण उनकी पार्टी आज एक डूबता हुआ जहाज की परिकल्पना को चरितार्थ करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जाता कि जब किसी के ताकत होती है, तो उसके पास अनेक लोग खड़े हो जाते हैं, और उसके शक्तिहीन होने पर कभी खास बनने वाले लोग भी दूरी बना लेते हैं। विपक्ष की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक समय ताल ठोकने वाली ममता बनर्जी के पास अब पहले जैसा रुतबा नहीं होगा और न ही विपक्ष में उनकी बात को कोई तबज्जो मिलेगा। इतना ही नहीं एक समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होने वाली ममता के लिए अब कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीति करने की मजबूरी बन गई है, जो ममता बनर्जी को न तो पहले स्वीकार था और न ही वे अब स्वीकार करेंगी।

जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के अपने दल से बागी होने की बात है तो यह कहना समीचीन ही होगा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष के भविष्य की संभावनाओं पर एक बहुत बड़ा विराम सा लगा हुआ दिखाई देता है। विपक्ष के राजनीतिक दल किसके नेतृत्व में एक होंगे, यह बड़ा सवाल है। जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ऐसे में क्षेत्रीय दलों के वे नेता जो हाँ में हाँ मिलाते हुए राजनीति करते थे वे अब प्रासंगिक होने लगे हैं। इनका प्रासंगिक होना ही विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि शक्ति केंद्र एक स्थान पर होता है तो उसकी बात का महत्त्व होता है, लेकिन यही शक्ति जब विभाजित हो जाती है, तब वह शक्तिहीन की श्रेणी में ही आती है। आज विपक्ष के राजनीतिक दल किसी एक दल के नेतृत्व में आने के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ तक क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की बात है तो वह कम से कम अपने प्रभाव क्षेत्र वाले राज्य में किसी दूसरे दल को अपने ऊपर प्रभावी होने नहीं देगा।

वर्तमान राजनीति का अध्ययन किया जाए तो विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला है। विपक्ष की ओर ये दोनों दल ही प्रभावी अस्तित्व में हैं। लेकिन कांग्रेस की नियति ऐसी हो गई है कि वह बिना किसी सहारे के आगे नहीं बढ़ सकती। उसको हमेशा क्षेत्रीय दलों की बैसाखी चाहिए। मुख्य बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के पास स्वयं की ताकत खत्म होती जा रही है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात है तो वह पारिवारिक पृष्ठभूमि से बने राजनेता होने के कारण केवल उत्तरप्रदेश की राजनीति तक ही सीमित हैं। यह बात सही है कि उत्तरप्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी के कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो उसकी प्रासंगिकता नहीं के बराबर ही होगी। विपक्ष के सपने को तार तार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद यह कहते हुए अलग हुए हैं कि ठाकरे की पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। यह बात शत प्रतिशत सही भी है। इसलिए जो नेता विचार की राजनीति के सहारे चल रहा था, उसको तालमेल बनाने में असहज ही होगा। इसके अलावा विपक्ष की पूरी राजनीति तुष्टिकरण को ज्यादा महत्त्व देने की रही है। यह विचार राष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यंत घातक है। आज देश को सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता है। देश की जनता भी ऐसा ही चाहती है। इसलिए विपक्षी दलों को जन भावनाओं के अनुसार ही चिंतन और मंथन करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो उनको भविष्य के सपने बुनने का भी अधिकार है। और इस पर ध्यान नहीं दिया तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब पूरी पार्टी में केवल कुछ ही नेता बचेंगे।

(लेखक- सुरेश हिंदुस्तानी)

प्रगति में जनजातीय समुदाय की भागीदारी

जब देश विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विकास यात्रा में देश के जनजातीय समुदायों की भूमिका क्या होगी? क्या विकास केवल शहरों, औद्योगिक केंद्रों और आर्थिक गलियारों तक सीमित रहेगा या फिर उन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तक भी पहुंचेगा, जहां सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन जीने वाले जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का हिमाचल प्रदेश दौरा इसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान जनजातीय क्षेत्रों के विकास, संवैधानिक अधिकारों, बुनियादी सुविधाओं और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। यह केवल एक प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि हिमाचल के जनजातीय भविष्य को नई दिशा देने का अवसर भी था। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में जनजातीय समुदायों का विशेष योगदान है। किन्नौर, लाहुल-स्पीति, भरमौर और पांगी जैसे क्षेत्रों ने सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं, लोककला और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखा है। इन समुदायों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है, जो आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट के दौर में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का विषय बन चुकी है।

इसके बावजूद यह भी एक सच्चाई है कि प्रदेश के अनेक जनजातीय क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं, संपर्क व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ हुई चर्चा के दौरान यह बात प्रमुखता से सामने आई कि जनजातीय विकास को केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, सांस्कृतिक संरक्षण और संतुलित विकास का विषय है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा केवल एक प्रशासनिक श्रेणी नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्तियों, विशेष विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का माध्यम भी है। हिमाचल प्रदेश में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र और समुदाय हैं जो जनजातीय जीवनशैली, संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े होने के बावजूद अपेक्षित सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हैं। विकास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय उपयोजनाओं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि यह धनराशि समय पर और प्रभावी ढंग से खर्च हो तथा इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार योजनाओं और जमीनी क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। यदि विकास का लाभ वास्तव में जनजातीय समाज तक पहुंचाना है, तो स्थानीय समुदायों, पंचायतों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को मजबूत बनाना होगा। जनजातीय क्षेत्रों के विकास की चर्चा सडक, स्वास्थ्य और शिक्षा के बिना अधूरी है। पांगी, भरमौर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोग आज भी मौसम की मार और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार खराब मौसम के कारण उनका शैक्षणिक जीवन प्रभावित होता है। ऐसी परिस्थितियों में सडक और डिजिटल कनेक्टिविटी केवल सुविधाएं नहीं बल्कि विकास की आधारशिला हैं। यदि जनजातीय क्षेत्रों को वर्षभर बेहतर संपर्क उपलब्ध हो जाए तो स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कृषि, बागवानी और रोजगार के नए अवसरों को अभूतपूर्व गति मिल सकती है। आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज भी कई जनजातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। टेलीमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और आधुनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से इन चुनौतियों को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों, छात्रावासों, डिजिटल शिक्षा सुविधाओं और कौशल विकास केंद्रों का विस्तार जनजातीय युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। विकास का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब हिमालय के अंतिम गांव में रहने वाला बच्चा भी वही अवसर प्राप्त कर सके जो किसी बड़े शहर में रहने वाले बच्चे को उपलब्ध हैं। आज आवश्यकता केवल सरकारी नौकरियों की नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित करने की भी है। जनजातीय युवाओं ने प्रशासनिक सेवाओं, सेना, शिक्षा, खेल, विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। यदि उन्हें अपने क्षेत्रों में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो पलायन की समस्या कम होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। किन्नौरी शॉल, भरमौर और पांगी के ऊनी उत्पाद, लाहुल के आलू और मटर, औषधीय पौधे तथा अन्य पारंपरिक उत्पाद स्थानीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बन सकते हैं। केंद्र सरकार की ह्यवन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्टह्न पहल इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

यदि इन उत्पादों को ब्रांडिंग, प्रसंस्करण, विपणन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए तो हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। लंबे समय तक सीमा से लगे गांवों को देश का अंतिम छोर माना जाता था, लेकिन अब उन्हें देश के प्रथम गांव के रूप में विकसित करने की सोच अपनाई जा रही है। सडक, संचार, पर्यटन, सामुदायिक सुविधाओं और स्थानीय आजीविका के माध्यम से इन गांवों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। हिमाचल के सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह पहल विशेष महत्व रखती है।

डा. जनक राज
विधायक, भरमौर

आलेख

चार महीने गोला बारूद तबाही लेकिन नतीजा सीफर

अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14-सूत्रीय कथित शांति समझौते से दशकों पुराने तनाव पर विराम लगने के कम ही आसार हैं। इस डील से वैश्विक स्तर पर शांति कायम होने की उम्मीद बेमानी है। ईरान पर लगे तेल निर्यात के आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में खुलकर कच्चा तेल बेच सकेगा और अरबों डॉलर कमा सकेगा। ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के फंड की रूपरेखा तैयार करने में सहयोग पर सहमति बनी है। ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने और होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी प्रबंधकीय भूमिका बनाए रखने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच महीनों से जारी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव को खत्म करके एक स्थायी युद्धविराम लागू किया गया है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया गया है, जिससे जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है।ईरान द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि वह भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।

आपको बता दें कि लगभग विगत 4 माह से अमरीका-इजरायल और ईरान के युद्ध ने न सिर्फ पश्चिम एशिया के क्षेत्र का ही भारी नुकसान किया, अपितु इसका विश्व भर के देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। खाड़ी देशों का तेल और गैस का उत्पादन बहुत कम हो गया। होर्मुज जलमार्ग और ईरान की नाकाबंदी के कारण आवागमन वाले जहाज रुक गए। इस मार्ग से लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस का निर्यात होता था। फैली इस गड़बड़ी ने जहां तेल और गैस की कीमतों को एक तरह आग लगा दी, वहीं खाद की सप्लाई रुक जाने से कृषि के लिए भी संकट खड़ा हो गया था। भारत द्वारा निर्यात किए जाते बासमती चावल और अन्य सामान की सप्लाई में भी रुकावट पड़ने से व्यापार बेहद घाटे में चला गया था। इसलिए फ्रांस में डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान में मसूद पेजेशिकयन द्वारा निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही समझौते पर डिजिटली हस्ताक्षर करने के बाद विश्व भर ने सुख की सांस ली है। यह संधि अंतरिम है। आगामी 2 माह तक सभी पक्षों द्वारा इस संबंध में विस्तारपूर्वक जरूरी पहलुओं पर बातचीत होगी, परन्तु ताजा जानकारी के अनुसार समझौते की कुछ धाराओं को लेकर अमरीका और ईरान के बीच पुन: कुछ मतभेद पैदा हो गए हैं।

ज्ञात हो कि संधि के संबंध में उठ रहे अनेक तरह के किन्तु परन्तु के कारण क्षेत्र में शांति होने संबंधी अभी भी विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखने की घोषणा की है। उसने लेबनान के 20 प्रतिशत क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया है। उसका तर्क है कि वहां सक्रिय हिज्बुल्लाह संबंधी इस समझौते में कोई फैसला नहीं किया गया। यदि यमन के हूती, हिज्बुल्लाह और हमास इजरायल के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखते हैं तो यह समझौता पूरी तरह सफल होना कठिन हो जाएगा। अमरीका द्वारा ईरान के विरुद्ध यह हमला शुरू किया गया था, जिसके संबंध में अब उसे नमोशी से गुजरना पड़ रहा है। वर्ष 1979 में 47 वर्ष पहले ईरान के शाह का तख्ता पलट कर वहां इस्लामिक शासन स्थापित किया गया था। उसके बाद अमरीका और अन्य यूरोपियन देशों द्वारा उस पर तेल और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे, जिस कारण ईरान को कड़ी समस्याओं में से गुजरना पड़ा। देश के भीतर इस्लामिक सरकार द्वारा अनेक तरह के प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण वहां ज्यादातर लोग, विशेष रूप से महिलाओं ने कई बार बगावत की,

परन्तु इन बगावतों को सख्ती से दबा दिया जाता रहा। खाड़ी देशों को भी लगातार ईरान से खतरा महसूस होता रहा है, जिसके लिए अमरीका ने इन देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाए थे। इजरायल के लिए भी वह इसी कारण खतरा बना रहा, क्योंकि हमास, हिज्बुल्लाह और हूती गुरिल्लों की वह इजरायल के विरुद्ध लगातार सहायता करता आया है। इस युद्ध में ईरान का बहुत भारी नुकसान हुआ। इसका ज्यादातर मूलभूत ढांचा तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही उसके सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और लगभग 40 मुख्य कमांडरों की भी हत्या कर दी गई थी। उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए और इन हमलों में हजारों ही लोगों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी मारे गए। ट्रम्प ने इस युद्ध से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हमला करके गिरफ्तार कर लिया था और वहां अपनी इच्छा से सरकार बना दी थी। शायद इसी भ्रम में ही इजरायल के उकसाने पर ट्रम्प ने ईरान पर हमला किया था, जो अमरीका जैसी बड़ी शक्ति के लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध हुआ। 4 माह तक यह युद्ध हवाई हथियारों से ही लड़ा गया परन्तु अपने भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने अमरीका के ठिकानों वाले 6 खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया और खाड़ी देशों में तेल सैक्टर के मूल ढांचे को भी अधिक सीमा तक नष्ट कर दिया। इजरायल का भी इस युद्ध के दौरान भारी नुकसान हुआ, परन्तु उसका इसमें हासिल यह रहा कि उसने भी हिजबुल्लाह, हूतियों और हमास का भारी नुकसान कर दिया है। आगामी समय में ईरान इन गुरिल्ला संगठनों की कितनी सहायता करने में समर्थ हो सकेगा, यह देखने वाली बात होगी, परन्तु इस सब कुछ के बावजूद अमरीका को इसलिए नमोशी सहन करनी पड़ी है क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर उसने यह युद्ध शुरू किया था वह अधूरे ही रह गए हैं। दूसरी तरफ ईरान इसमें मजबूत होकर निकला है। इस समझौते में ईरान ने होमुर्ज. जल मार्ग बिना शर्त खोलने पर सहमति दी है परन्तु उसकी ओर से परमाणु बम बनाने या यूरेनियम को भरपूर बनाने की सीमा निश्चित करने संबंधी अभी फैसला नहीं लिया गया। ट्रम्प इस बात से संतुष्टि प्रकट कर सकते हैं कि उन्होंने होमुर्ज जल मार्ग खोलने के लिए ईरान को सहमत कर लिया है और ईरान को परमाणु बम न बनाने के लिए भी सहमत कर लिया है। ट्रम्प ने समझौते के लिए इस कारण भी जल्दबाजी की है कि आगामी नवम्बर माह में अमरीका में मध्यकालीन चुनाव होने जा रहे हैं। वह इस समझौते को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान को अब यह लाभ भी मिल गया है कि उस पर 47 वर्ष पहले लगाए गए प्रतिबन्ध समाप्त हो गए हैं। वह अपनी इच्छा से तेल का निर्यात कर सकेगा और उसकी विदेशों में प्रतिबन्धित सम्पत्तियों संबंधी भी छूट मिल जाएंगी।

ईरान ने इस संधि द्वारा इस बात पर भी सफलता हासिल की है कि उसके मूलभूत ढांचे के हुए बड़े नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए उसे 28 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि भी खाड़ी देशों को देनी पड़ेगी, जबकि इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अमीरात, कुवैत, कतर और सऊदी अरब का भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत के लिए यह समाचार कई तरह से राहत वाला है। यह अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए लगभग 85 प्रतिशत तेल आयात करता है। होमुर्ज जल मार्ग के खुलने से उसे लाभ होगा। ईरान पर प्रतिबन्ध हटाए जाने से भारत उससे भी तेल खरीद सकेगा और चाबहार बंदरगाह, जिसके निर्माण पर भारत ने अब तक 1400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, उसके भी पुन: खुलने से भारत-ईरान द्वारा अफगानिस्तान और केन्द्रीय एशिया के देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को भारी बल दे सकता है। इसलिए इस समझौते से भारत सहित विश्व भर के देशों ने कुछ राहत महसूस की है।लेकिन अमेरिकी बिगड़ैल सांड कब दोबारा अशांति फैलाने के लिए हरकत मे आ जाए कहना कठिन है।

लेखक – मनोज कुमार अग्रवाल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

दिल्ली में सरकारी सेवाओं की तय समय सीमा

23 नई सेवाएं टाइम बाउंड डिलीवरी सिस्टम में शामिल

दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस निर्णय से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों व आम जन को सीधे लाभ मिलेगा।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक पत्रकार विज्ञप्ति में कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। इससे अनावश्यक देरी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या में कमी आएगी। सरकार दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था न केवल नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करेगी बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में ह्यईज ऑफ डूइंग बिजनेसह्न को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार भी ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रही है जिनसे उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम द्वारा फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली मीटर से संबंधित आवेदन और कनेक्शन समझौते की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत दुकानों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत बैटरी अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन एवं पुनर्चक्रण से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक प्राधिकरण-पत्र (ऑथराइजेशन) 15 दिनों में जारी किया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नगर निगम से संबंधित सेवाओं में वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण तथा मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति, खाद्य व्यवसाय के लिए राज्य लाइसेंस के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी, होटल पंजीकरण या संचालन अनुमति तथा बूचड़खाना लाइसेंस सभी को 60 दिनों में जारी किया जाएगा। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में तथा निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति केवल एक दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक नियंत्रण संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस की प्रक्रियाएं 21-21 दिनों में पूरी की जाएंगी। आबकारी विभाग के अंतर्गत बार लाइसेंस 30 दिनों में, आईएमएफएल श्रेणी के ब्रैंड एवं लेबल पंजीकरण 42 दिनों में और एफएल श्रेणी के ब्रांड लेबल पंजीकरण 42 दिनों में किए जाएंगे।

...और विकास की प्रक्रिया को गति मिले

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी अनुमति के आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड कटिंग व उससे जुड़े अन्य कार्यों से संबंधित अनुमति 45 दिनों में प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त रेरा के अंतर्गत बिल्डर पंजीकरण तथा रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें प्रत्येक नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवा मिले, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की प्रक्रिया को गति मिले।

संक्षिप्त वार्ता

अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल, एक्स पर दी जानकारी

वेब वार्ता, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी शक्रवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि वह आगामी शुक्रवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। उन्होंने आगे कहा कि वह शुक्रवार को श्री राम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चंदे में कथित हेराफेरी का मामला जून महीने के शुरूआती दिनों में तब सामने आया, जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंतरिक ऑडिट में भारी विसंगतियां मिलने के आरोप लगे।

बिना लाइसेंस के कार चला रही युवती ने सिपाही को कुचला

वेब वार्ता, नई दिल्ली। अशोक विहार में बिना लाइसेंस के कार चला रही एक युवती ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को कुचल दिया। नांगलोई का रहने वाला सिपाही जितेंद्र कुमार घटना के समय बाइक से थाने जा रहा था। दोनों पैरों पर कार का पहिया चढ़ने से वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने उसे दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया। कार चला रही युवती की पहचान 19 साल की ओशिन गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, 28 साल का जितेंद्र कुमार परिवार के साथ नांगलोई में रहता है और दिल्ली पुलिस में सिपाही है। उसकी तैनाती अशोक विहार थाने में है। अशोक विहार थाने में दर्ज प्राथमिकी में सिपाही ने बताया कि 19 जून की रात एक शव बाबू जगजीवन राम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के बाद वह बाइक से अशोक विहार थाने की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक कार ने अचानक बांयी ओर मोड़कर उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गिर गया। इतने में भी चालक ने कार नहीं रोकी और दोनों पैरों पर चढ़ा दी। बाइक पहिये के पास आने से कार रुक गई। उसे पैरों में काफी चोट लगी।

बिजली कंपनियों का सीएजी से होगा ऑडिट, नहीं बढ़ने देंगे दाम

वेब वार्ता, नई दिल्ली। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने च्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा सीएजी ऑडिट का विरोध करने के लिए दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इससे उनके ऑडिट का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि अब सीएजी ऑडिट से संबंधित सुनवाई उपराज्यपाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों द्वारा हाई कोर्ट में सीएजी ऑडिट का विरोध करने के लिए जाने से आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद केजरीवाल और बिजली कंपनियों के बीच चल रही मिलीभगत की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने उजागर हो गई है। दिल्ली सरकार ने पूरे राजनीतिक इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ हाई कोर्ट में दिल्ली की जनता के हितों का पक्ष रखा।

निजी व्यवसायिक शोधपत्रों को प्राथमिकता देना बंद करे डीयू

वेब वार्ता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक सघ नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) के अध्यक्ष डॉ.एके भागी ने दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) एवं शैक्षणिक परिषद (एसी) के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक खुला पत्र लिखकर यूजीसी विनियम-2018 को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने तथा शिक्षकों की पदोन्नति एवं नियुक्तियों में आ रही बाधाओं और विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एनडीटीएफ ने आरोप लगाया है कि स्थापित विश्वविद्यालयों एवं सरकारी संस्थानों की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध को अस्वीकार करते हुए निजी व्यवसायिक इंडेक्सिंग प्रणालियों और शोधपत्रों को प्राथमिकता देने से योग्य शिक्षकों के हित प्रभावित हुए हैं और दशकों के संघर्ष से स्थापित शिक्षक-हितैषी पदोन्नति व्यवस्था कमजोर हुई है।

डीयू के विज्ञान विभागों में धन की कमी से प्रयोगशालाओं पर संकट

शिक्षकों ने जताई चिंता

दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञान विभागों में प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। शिक्षक प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध बजट के बीच बड़ा अंतर है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध गतिविधियों पर पड़ सकता है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सचिव प्रो. बिमलेन्दु तीर्थाकर ने कहा कि विज्ञान विभागों को शिक्षण और प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों की खरीद और उनके रखरखाव में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण प्रभावित हो रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि विज्ञान विषयों की पढ़ाई में आधुनिक प्रयोगशालाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि समय पर उपकरणों का उन्नयन और रखरखाव नहीं किया गया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास और शोध कार्यों पर पड़ सकता है।

इस मुद्दे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों से भी जोड़ते हुए प्रो. राजेश झा ने कहा कि नई शिक्षा नीति बेहतर शिक्षण वातावरण के निर्माण पर बल देती है, जिसके लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कक्षाएं और तकनीकी संसाधन आवश्यक हैं।

ऐसे में विज्ञान विभागों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना अत्यंत जरूरी है। प्रो. झा ने दावा किया कि कई विभागों को अपनी प्रयोगशाला सुविधाओं के उन्नयन और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें जरूरत की तुलना में काफी कम धनराशि आवंटित की जा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक विभाग को प्रयोगशाला उपकरणों के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जबकि उसे केवल लगभग 60 लाख रुपये ही उपलब्ध कराए गए।

जवाब प्राप्त नहीं हो सका

शिक्षक प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से विज्ञान विभागों की वित्तीय जरूरतों का पुनर्मूल्यांकन करने और प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और शोध सुविधाएं मिल सकें। इस संबंध में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक जवाब प्राप्त नहीं हो सका।

डिस्पेंसरी ही बीमार? न्यू सीमापुरी डिस्पेंसरी के मुख्य द्वार पर जलभराव

राजधानी दिल्ली के न्यू सीमापुरी स्थित डिस्पेंसरी, जो स्थानीय लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इन दिनों अपनी बदहाल व्यवस्था के कारण चर्चा में है। डिस्पेंसरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर गंदे पानी का स्थायी जलभराव न केवल मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, बल्कि संक्रमण और बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा रहा है।

वेब वार्ता, नई दिल्ली। अब्दुल रशीद

न्यू सीमापुरी डिस्पेंसरी, जो सीएनजी पंप के समीप स्थित है, वहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज दवा लेने और इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही लोग डिस्पेंसरी के गेट पर पहुंचते हैं, उनका सामना गंदे और बदबूदार पानी से होता है। मरीजों को इसी पानी के बीच होकर अंदर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

मरीजों की बढ़ी परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि विडंबना यह है कि जहां लोग बीमारियों से राहत पाने के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरी का रुख करते हैं, वहीं प्रवेश द्वार पर फैला गंदा पानी स्वयं कई बीमारियों को निमंत्रण देता दिखाई दे रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ सकता है।

क्षेत्र के निवासियों और मरीजों का आरोप है कि इस समस्या की ओर संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि जब राजधानी के स्वास्थ्य केंद्रों की यह स्थिति है, तो स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे सवालों के घेरे में आ जाते हैं।

मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को गंदे पानी से होकर गुजरने में सबसे अधिक परेशानी होती है। कई बार फिसलने और दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। स्थानीय नागरिकों ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि डिस्पेंसरी के मुख्य द्वार पर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा नियमित सफाई कराकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

अब बड़ा सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र ही गंदगी और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, तब आम नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह केवल असुविधा का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

फर्जी फर्मों के जरिए साइबर ठगी का जाल

दिल्ली पुलिस ने चार आरोपित दबोचे

वेब वार्ता, नई दिल्ली। मध्य जिला पुलिस की साइबर थाना इकाई ने एक अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों को फर्जी बैंक खाते, भुगतान मशीनें और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर ठगी के नेटवर्क को संचालित करने में मदद कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर एसीपी साइबर सेल और थाना साइबर पुलिस की टीम ने पहाड़गंज स्थित एक होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चार आरोपितों को उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वे साइबर अपराधियों को बेचने के लिए बैंकिंग ढांचा तैयार कर रहे थे। मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान आनंद पर्वत निवासी संजय, पटेल नगर निवासी कुलदीप गोले, हरियाणा के सोनीपत जनपद के गोहाना निवासी निर्दोष बिदलान तथा राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी दीपक बिश्नोई के रूप में हुई है।

जांच में सामने आया है कि यह गिरोह बेहद संगठित तरीके से कार्य कर रहा था। गिरोह के सदस्य फर्जी किरायानामा तैयार कर 'एसजी एंटरप्राइजेज', 'जीएम एंटरप्राइजेज' और 'एचएम ट्रेडर्स' जैसी फर्जी साझेदारी फर्मों का गठन करते थे। इसके बाद इन फर्मों के नाम पर वाणिज्यिक चालू खाते खुलवाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि इन खातों में जमा की जाती थी। इसके बाद भुगतान मशीनों और व्यापारी आधारित त्वरित भुगतान संकेतों का उपयोग कर अवैध धन को वैध व्यापारिक लेनदेन के रूप में दशार्या जाता था। खाता उपलब्ध कराने वालों को लगभग 8 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था, जबकि एजेंट आपस में अतिरिक्त कमीशन का बंटवारा करते थे।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक सक्रिय भुगतान मशीन, व्यापारी भुगतान संकेत स्कैनर, पांच वाणिज्यिक खातों की चेक पुस्तिकाएं और पासबुक, छह सक्रिय डेबिट कार्ड, साझेदारी संबंधी दस्तावेज, रबर मोहरें, स्थायी खाता संख्या पत्र, वाणिज्यिक किरायानामे और बैंकिंग रिकॉर्ड से भरे चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तकनीकी जांच में यह भी सामने आया है कि जब्त किए गए कई बैंक खाते पहले से ही देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज साइबर ठगी के मामलों से जुड़े हुए हैं। कुछ खाते कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं से भी संबंधित पाए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतों में इन खातों का उल्लेख मिला है। जांच के दौरान कुछ बैंक खातों का संबंध पांच-पांच अलग-अलग साइबर ठगी मामलों से भी जुड़ा पाया गया है। अदालत ने चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की धन शृंखला की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा अब तक कितनी राशि की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है।

बदरपुर के वार्डों को ओ-जोन से हटाने की मांग

वेब वार्ता, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर की कई कॉलोनियों को ओ-जोन से निकालकर एफ जोन में करने की मांग की गई है। स्थानीय नागरिक बदरपुर के तीन वार्ड हरि नगर, मीठापुर और जैतपुर को ओ-जोन से निकालकर एफ जोन में डालने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसे लेकर लोग क्षेत्र में मार्च भी निकाल रहे हैं।

इस संबंध में समाजसेवी सरजीत चौकन ने बताया कि इन कॉलोनियों के निवासियों की चिंता तब बढ़ गई जब यहां पर ओ-जोन से जुड़े बोर्ड लगे और लोगों में तोड़फोड़ का भय उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को जनप्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि क्षेत्र में तोड़फोड़ नहीं होगी। हमारी मांग है कि इस संबंध में प्रशासन लिखित अधिकारिक आदेश जारी करे।

विदेश जाने के लिए अभिनेत्री को शर्तों में ढील देने से इनकार

वेब वार्ता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री संदीपा विर्क संबंधी सत्र अदालत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने अभिनेत्री को विदेश यात्रा से पहले सुरक्षा रकम के तौर पर 20 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडी) देने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह शर्त उचित है। उसके खिलाफ धनशोधन का मामला चलने तक भारत लौटने के लिए जरूरी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने विर्क की याचिका खारिज कर दी। अभिनेत्री ने तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सेशन जज के आदेश को चुनौती दी थी। सेशन जज ने 15 जून से 15 जुलाई, 2026 के बीच अभिनेत्री का पासपोर्ट जारी करने व फ्रैंकफर्ट, जर्मनी जाने की इजाजत देने के लिए लगाई गई शर्तों में ढील देने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा कि सत्र अदालत द्वारा लगाई गई शर्तें खास तौर पर यह पक्का करने के लिए थीं कि याचिकाकर्ता समय पर भारत लौट सके। विर्क की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें मेसर्स फोक स्टूडियोज से अभिनय का प्रस्ताव मिला है। उन्हें प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाना है। यह तर्क दिया गया कि लंबित आपराधिक कार्यवाही व उससे जुड़े आरोप की वजह से अभिनेत्री मौजूदा कार्य के अलावा काम के मौके नहीं मिल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनकी काफी संपत्ति पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज या जब्त कर दी गई है। इसलिए उसके पास 20 लाख रुपये की एफडीआर देने के लिए राशि नहीं है। हालांकि पीठ ने आर्थिक दिक्कत की दलील को सही नहीं पाया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलाजाब हादसों के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, आर्थिक सहायता देकर जताई संवेदना

नई दिल्ली। अब्दुल रशीद

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को मालवीय नगर और सैदुलाजाब में हुई दुखद घटनाओं में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारों के बीच पहुंचकर उन्हें ढांढस बंधाया और दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समय प्रभावित परिवारों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है और दिल्ली सरकार इस कठिन घड़ी में उनके साथ पूरी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी अपने को खोने की पीड़ा की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों और एजेंसियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी विभागों को जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार न केवल राहत और सहायता प्रदान करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिए भी ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को और अधिक मजबूत एवं जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे, ताकि नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राहत एवं सहायता कार्यों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी तथा सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी।

संक्षिप्त वार्ता

देवरिया जिले में नीट परीक्षा सकुशल संपन्न

वेब वार्ता, देवरिया 21 जून

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रविवार को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां के साथ पूरी की। परीक्षा के लिए जिले में कुल 14 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट व 14 स्टेटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम रहें।

नीट यूजी में प्रवेश पाने के रविवार को जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर बाद 2 से 5 .15 बजे तक परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 5702 अभ्यर्थी में शामिल हुए। इसके लिए जिले के जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उनमें बीआरडी पीजी कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक गोरखपुर रोड, लाला करमचंद थापर इंटर कालेज बैतालपुर, राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर, जनता इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना, अशोक इंटर कॉलेज डुमरी रामपुर कारखाना, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज गरुणपार, राजकीय इंटर कालेज कोतवाली रोड, दीनानाथ राजकीय महिला पीजी कॉलेज सीसी रोड, गंगा प्रसाद इंटर कॉलेज मझगांवा, बाबा राघव दास इंटर कॉलेज न्यू कॉलोनी, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज जलकल रोड, जनता इंटर कॉलेज सोनूघाट, शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुन्दू शामिल रहे।

कुशीनगर में छोटी गंडक में मिला वृद्ध महिला का बोरे में शव

कुशीनगर 21 जून

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में छोटी गंडक नदी के सिकटिया गड़ेरीपट्टी घाट पर शनिवार को 65 वर्ष की महिला का शव बोरे में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शव देख कोतवाली पुलिस को सूचना दी।जांच पड़ताल कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस के अनुसार जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के गड़ेरीपट्टी घाट पर आज दोपहर दो बजे गंडक नदी में नहा रहे लोगों ने बोरे में शव देखा। बोरे में शव होने की खबर कुछ ही देर में इलाके में फैल गई। पुलिस आ गई।बोरे को बाहर निकाल पुलिस ने खुलवाया तो महिला का शव मिला। शव की पहचान के लिए पुलिस ने जरूरी कदम उठाए, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। जांच पड़ताल कर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी की।महिला का शव कफन से ढका था। पैर व गले में ईंट बंधा था। फारेंसिक टीम बुलाई गई। टीम ने जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किया।

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे ने बताया कि महिला झारंखड राज्य की प्रतीत हो रही। शव यहां कैसे पहुंचा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर मृत्यु का कारण साफ हो जाएगा.

किशोरी ने बहन से झगड़े के बाद नहर में लगाई छलांग

कुशीनगर 21 जून

घर में छोटी बहन से किसी बात को लेकर कहासुनी होने व फिर हुई हाथापाई के बाद किशोरी ने जानलेवा कदम उठा लिया। गांव के बाहर बहने वाली नहर में जाकर छलांग लगा दी। गुजर रहे तीन राहगीरों ने जान बचाई और बाहर निकाला।प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने राजकीय मेडिकल कालेज कुशीनगर के अस्पताल रेफर कर दिया। घटना शनिवार को दोपहर बाद चार बजे विशुनपुरा थाने के मुख्य पश्चिमी गंडक नहर में नेटुवा वीर बाबा पुल के समीप हुई। परिजन के अनुसार, बैकुंठपुर गांव की काजल कुमारी घर में सोई थी। इस दौरान छोटी बहन प्रीती से किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। छोटी बहन से पिटे जाने की बात उसे नागवार लगी। फिर वह घर से मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के पुल पर आकर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छलांग लगा दी। इस दौरान घर जा रहे तीन राहगीरों ने नहर में छलांग लगा कर काजल को पानी से बाहर निकाल कर उसे दुदही सीएचसी में भर्ती कराया।

30 जून तक गुणवत्ता के साथ पूरे हों गोद लिए विद्यालयों के कार्य : डीएम

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए विद्यालयों में चल रहे विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं और अन्य कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए विद्यालयों में कराए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालयों में खिड़की-दरवाजों की मरम्मत, टाइल्स लगाने तथा आकर्षक वाल पेंटिंग का कार्य तेजी से कराया जाए, ताकि बच्चों में विद्यालय के प्रति रुचि और सकारात्मक वातावरण विकसित हो सके। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को 30 जून तक कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

शारदा नहर पर निर्माणाधीन पुल में हादसा, भारी बीम गिरने से दो मजदूर घायल

वेब वार्ता, हरदोई

लखनऊ-शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-731) पर शेदपुर स्थित शारदा नहर के ऊपर निमार्णाधीन पुल पर सोमवार सुबह निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पुल पर बीम स्थापित करते समय भारी बीम अचानक नीचे गिर गई, जिससे दो मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए निर्माण कार्य प्रभावित रहा।जानकारी के अनुसार थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र में निमार्णाधीन ओवरब्रिज पर सुबह करीब 10:20 बजे बीम को उसके निर्धारित स्थान पर रखा जा रहा था। इसी दौरान बीम का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। हादसे में राहुल पुत्र छोटेलाल तथा राजेश्वर पुत्र गेंदालाल घायल हो गए। मौके पर मौजूद श्रमिकों और अधिकारियों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हरदोई मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवाया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

प्रशासन की देखरेख में गिरी हुई बीम को हटाने का कार्य शुरू कराया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग एवं निर्माण एजेंसी को हादसे के कारणों की जांच कराने तथा निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे में दो लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौके पर कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

निमार्णाधीन परियोजना में हुई इस दुर्घटना ने कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग सुधारने पर जोर, खराब प्रदर्शन वाले विभागों को चेतावनी

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में सोमवार को विवेकानंद सभागार में विकास कार्यों से संबंधित विभागों की सीएम डैशबोर्ड प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन वाले विभागों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति परिलक्षित होती है, जिसकी नियमित समीक्षा शासन स्तर पर की जाती है। प्रत्येक माह प्रदेश के सभी जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है, इसलिए सभी विभाग अपने

कार्यों की सतत समीक्षा करें और रैंकिंग में सुधार के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय पोर्टलों पर सूचनाओं की समयबद्ध एवं शत-प्रतिशत फीडिंग की जाए ताकि योजनाओं की वास्तविक स्थिति सही रूप में प्रदर्शित हो सके। बैठक में जनपद में संचालित निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों को समय से हैंडओवर कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा योजनाओं की कार्ययोजना समय से प्रस्तुत करें। उन्होंने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।

अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर पर भड़क उठे आनंद भदौरिया

सीतापुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ लगे विवादित पोस्टरों को लेकर उत्तर प्रदेश का राजनीति में हलचल है. इसी बीच यूपी की धौराहरा लोकसभा सीट से सपा सांसद आनंद भदौरिया का एक अलग अंदाज देखने को मिला है. राजधानी लखनऊ और सीतापुर समेत यूपी के कई जिलों में अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर लगे हैं, जिन्हें उतारने के लिए सपा सांसद आनंद भदौरिया खुद पोल पर चढ़ गए. सीतापुर में सड़क किनारे लगे पोल और दीवारों पर अखिलेश यादव के विरोध वाले पोस्टर लगे थे.

अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं, आरोपियों पर तत्काल करें कार्रवाई : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हर फरियादी से एक-एक कर मुलाकात की. उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों के उचित व समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया. वहीं अतिक्रमण की शिकायत पर सीएम योगी सख्त हुए और तत्काल इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया. 'जनता दर्शन' में मथुरा से एक भी शिकायत लेकर पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि चकरोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है. इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई.

योग से रोग भगाए, स्वस्थ रहें सब लोग'

किसान इंटर कॉलेज के स्वयंसेवकों ने सामूहिक योग कर दिया निरोग रहने का संदेश

कुशीनगर 21 जून। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला क्षेत्र के नागरिकों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से किसान इंटर कॉलेज, पिपरा बाजार में 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' के अंतर्गत एक भव्य सामूहिक योग शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना (ठरर) की सामान्य गतिविधियों के तहत आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं और शिक्षक-कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

विद्यालय परिसर के प्रांगण में कार्यक्रम की शुरूआत सामान्य योग

प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह 7:30 बजे प्रार्थना और ओंकार ध्वनि के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में स्वयंसेवकों और छात्र-छात्राओं ने ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। इसके साथ ही कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से मानसिक एकाग्रता और तनाव मुक्ति का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने ₹करें योग, रहें निरोग₹ और ₹स्वस्थ तन, सुंदर मन₹ जैसे नारों से ग्रामीणों को भी जागरूक किया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. विष्णु प्रताप चौबे ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योग दिवस का मुख्य लक्ष्य योग को केवल एक दिन का उत्सव न बनाकर इसे जन-आंदोलन का रूप देना है। उन्होंने बताया कि विद्यालय स्तर पर छात्रों को योग के प्रति जागरूक करना है ताकि वे मानसिक रूप से सुदृढ़ बन सकें।स्वयंसेवकों के माध्यम से निकटवर्ती ग्रामों (पिपरा बुजुर्ग, मिठहा माफी और चितहा) में जागरूकता अभियान चलाकर प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक योग के महत्व को पहुँचाना है।

उत्सव को उपद्रव में बदलना ही सपा का काम रहा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

फिरोजाबाद, 22 जून (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसके एजेंडे में विकास नहीं, बल्कि समाज को बांटना, सामाजिक एकता को कमजोर करना और उत्सवों को उपद्रव में बदलना शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास, विरासत और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पहचाना जा रहा है।

मुख्यमंत्री सोमवार को फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 81 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में टुंडला क्षेत्र की 452 करोड़ रुपये तथा शिकोहाबाद क्षेत्र की 206 करोड़ रुपये लागत की विकास योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में ₹एक जिला-एक उत्पाद₹, ₹एक जिला-एक व्यंजन₹ और ₹एक जिला-एक मेडिकल कॉलेज₹ जैसी योजनाएं दे रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के समय ₹एक जिला-एक माफिया₹ की स्थिति थी।

नचौरी में बहू बेटी सम्मेलन, महिलाओं को दहेज व बाल विवाह के खिलाफ किया गया जागरूक

गैसड़ी / बलरामपुर। थाना कोतवाली गैसड़ी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत ग्राम नचौरी में बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने महिलाओं व बालिकाओं को दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूक किया। बताया गया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

वेब वार्ता, कमर खान

सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही वूमेन पावर लाइन 1090, एंबुलेंस सेवा 108, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, गर्भवती महिलाओं के लिए 102, साइबर हेल्पलाइन 1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसे महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी भी दी गई।

जानकारी भी दी

कार्यक्रम के दौरान पंपलेट वितरित किए गए और महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं, लेकिन किसी ने

कोई विशेष समस्या नहीं बताई। पुलिस ने सभी को कानून का पालन करने और किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की अपील की। साथ ही थाना स्तर पर संचालित मिशन शक्ति केंद्र और महिला साइबर सेल के बारे में भी जानकारी दी.

कार्यकताओं के संघर्ष, परिश्रम एवं समर्पण से भामस देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन: श्रीराम

कानपुर। भारतीय मजदूर संघ महानगर जिला इकाई द्वारा बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज, बेनाझाबर, कानपुर में जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्रीराम सिंह तथा मुख्य वक्ता भारतीय मजदूर संघ उत्तर-मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि व प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश यादव, प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना राजपूत द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात जिला पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र पहनाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक श्रीराम ने कहा कि संघ की प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के संघर्ष, परिश्रम एवं समर्पण के आधार पर आज देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए उद्योगहित एवं कर्मचारीहित को लेकर कार्य कर रहा है। प्रांत प्रचारक ने संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों, विशेषकर पंच परिवर्तन के विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।

आटा पिसाकर लौट रहे व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

हरदोई। थाना बेनीगंज क्षेत्र के ग्राम घरौली में रविवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब आटा पिसवाकर घर लौट रहे एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है।

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घरौली निवासी पलविंदर सिंह (55) पुत्र लखवीर सिंह रविवार शाम करीब आठ बजे पास के गांव अटवा मुठिया स्थित आटा चक्की से आटा पिसवाकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अपने झाले के निकट पहुंचे, तभी मोटरसाइकिल से आए कुछ

अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली उनके सीने के दाहिने हिस्से में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालत स्थिर है और उनका उपचार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल और उसके परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। परिजनों की ओर से तहरीर प्राप्त होने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा घटनास्थल के आसपास के संभावित साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। दिनदहाड़े नहीं बल्कि शाम के समय हुई इस फायरिंग की घटना से गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण ख़बर

रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा हमला

- मॉस्को। यूक्रेन ने मॉस्को रिफाइनरी के बाद रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी पर हमला किया है। रूस के पश्चिमी साइबेरिया में स्थित इस तेल रिफाइनरी को यूक्रेन ने दो हजार किलोमीटर दूर से निशाना बनाया है। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास अब ऐसे नए ड्रोन आ गए हैं, जो कि 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमारे ड्रोन रूस के ट्यूमेन इलाके तक पहुंचे। यह रूस-यूक्रेन की सीमा से दो हजार से ज्यादा किलोमीटर दूरी पर है।

हमारे काबिल इंजीनियरों ने ऐसी ड्रोन तकनीक विकसित की है कि अब रूस के दूरदराज के इलाकों में स्थित उसके सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को अचूक हमले के लिए बधाई दी। बीते कई महीनों से यूक्रेन, रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले कर रही है। इन हमलों के लिए यूक्रेनी सेना मीडियम व लॉन्ग रेंज मिसाइलों का उपयोग कर रही है।

स्टंटबाज का पुलिस को खुला चैलेंज!

- दुर्ग। जिले में अपराधी और स्टंटबाज युवकों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण भिलाई में देखने को मिला है। सड़क पर खतरनाक बाइक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए युवक ने पुलिस कार्रवाई का मजाक उड़ाते हुए पुलिस वाहन के अंदर से ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में युवराज सोनी को गिरफ्तार किया था।

शांति वार्ता के बीच अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, होर्मुज स्ट्रेट बंद किया, तो नहीं बचेगा ईरान

तेहरान/वाशिंगटन डीसी

ईरान और अमरीका में शांति वार्ता के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि वह लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका, तो अमरीका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा। अमरीकी राष्ट्रपति ने साफ-साफ कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की जुर्रत की, तो उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि आप इसे बंद करेंगे और आपके पास कोई देश नहीं बचेगा। आप अपने देश वापस भी नहीं जा पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर अमरीका इस रणनीतिक जलमार्ग पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। उन्होंने एक कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी, तो हम होर्मुज जलडमरूमध्य पर कब्जा करेंगे। अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं, तो हम खुद वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेंगे। ट्रंप की धमकी से पहले ईरान ने इस महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद करने की बात कही थी।

92 फीसदी इजरायली बोले, समझौते से ईरान को ज्यादा फायदा

अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते को लेकर इजरायल में हुए एक सर्वे में 92 फीसदी लोगों ने माना कि इस डील से ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है। सर्वे के मुताबिक, बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों का मानना है कि युद्ध के बाद हुए समझौते में तेहरान को आर्थिक और कूटनीतिक लाभ मिला, जबकि इजरायल को अपेक्षित राजनीतिक बढ़त नहीं मिल सकी। सर्वे में शामिल 78 फीसदी लोगों ने यह भी माना कि अमरीकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पीछे छोड़ दिया और अंतिम समझौते की दिशा तय करने में वाशिंगटन की भूमिका ज्यादा प्रभावी रही।

स्विट्जरलैंड में अमरीका और ईरान में शांति पर वार्ता

जेनेवा। स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में रविवार को अमरीका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो गई है।

अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वार्ता के दौरान कहा कि पिछले कुछ घंटों में अच्छी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान मिलकर शांति और समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। वेंस के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय शुरू हो और अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल जाए। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़या है।

राम मंदिर में 200 किलो चांदी की ईंटों पर विवाद

सिंधी समाज को 5 साल बाद भी नहीं मिली रसीद

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक नए विवाद के केंद्र में आ गया है। इस बार सिंधी समाज ने मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका कहना है कि उन्हें आज तक इन दान की गई ईंटों की कोई रसीद या आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजू मनवानी के अनुसार, 26 जनवरी 2021 को दुनिया भर के सिंधी समाज के सहयोग से ये चांदी की ईंटें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को कारसेवक पुरम में सौंपी गई थीं। इन ईंटों पर समाज के पूजनीय देवता झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी और इस कार्यक्रम में 12 विभिन्न देशों के सिंधी प्रतिनिधि उपस्थित थे। डॉ. मनवानी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि चांदी की जांच के बाद उन्हें दान की रसीद प्रदान की जाएगी, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ।

डॉ. मनवानी का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावे और निर्माण कार्यों में कथित हेराफेरी को लेकर चल रही हालिया खबरों के बाद उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब सिंधी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के क्रियाकलापों पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से महिपाल जैसे पूर्व कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्तियों ने चढ़ावे की रकम में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और निर्माण कार्य में व्यापक घोटाले के आरोप लगाए हैं। इसी तरह, रोकडिया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा ने भी दावा किया है कि उनके जौनपुर के शिष्य अजय विश्वकर्मा द्वारा दान किए गए रामलला के लिए सुंदर हार और चरण पादुका की रसीद एक साल बाद भी ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इन संगीन आरोपों के बाद, मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसआईटी ने पहले चरण की जांच में कुछ शुरुआती पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है और अब दूसरे चरण में उन सभी लोगों से पूछताछ करने की तैयारी में है जिन्होंने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ट्रस्ट पर विभिन्न आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य उनके दावों की सत्यता का पता लगाना है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। महिपाल, जिन्होंने पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए थे, बाद में किसी चैनल या मंच पर नजर नहीं आए और उन्होंने लोगों के फोन उठाना भी बंद कर दिया। एसआईटी की जांच अब इन्हीं जैसे आरोपों की तह तक जाने का प्रयास करेगी।

ईरान-अमेरिका जंग से जब दुनिया परेशान थी तब भारत ने व्यापार का विविधीकरण किया

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान में कई दिन चली जंग के बाद समझौता हो गया। भले ही दोनों देशों ने हमले रोक दिए हों और होर्मुज फिर से ऑपरेशनल हो चुका है, लेकिन 28 फरवरी से लेकर 18 जून तक दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर पड़ा। इस दौरान भारत ने देश को नुकसान से बचाने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बड़े रणनीतिक कदम उठाए। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट की सप्लाई चैन बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। ऐसे में भारत ने अपने व्यापार का तेजी से विविधीकरण किया। व्यापार में विविधीकरण भारत की रणनीति रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ तनाव से भरे संबंध और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया।

बिहार में नीट री-एग्जाम सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, 24 गिरफ्तार

पटना। बिहार के लखीसराय में नीट री-एग्जाम के दौरान पुलिस ने एक बड़े सॉल्वर गैंग के नेटवर्क का पदार्फाश किया है। यह गिरोह असली अभ्यर्थियों की जगह फर्जी प्रॉक्सी (नकली परीक्षार्थियों) को बैठाकर परीक्षा दिलाने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 मेडिकल छात्र और परीक्षा प्रक्रिया संभाल रही बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी भी शामिल हैं। इस खुलासे ने परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी और इसमें शामिल लोगों के व्यापक नेटवर्क की ओर इशारा किया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों के छात्र और परीक्षा केंद्र पर पहचान व उपस्थिति दर्ज करने का काम संभाल रही बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस गिरोह का कथित मुख्य सरगना गया के अन्नपूर्णा नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का छात्र अर्पित राज बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अर्पित राज से 2024 के नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है, जो इस नेटवर्क की जड़ों को और गहरा दशार्ता है। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र मयंक कश्यप बायोमेट्रिक कंपनी का फर्जी स्टाफ बनकर हसनपुर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के अंदर घुस गया था। पुलिस जांच के दौरान मयंक को सबसे पहले पकड़ा गया। मयंक से हुई पूछताछ ने पुलिस को इस गिरोह के अन्य ठिकानों और सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मयंक की निशानदेही पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए केआरके हायर सेकेंडरी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय लखीसराय में छापेमारी की।

दिये सख्त निर्देश

जांच में यह भी पता चला है कि इस गिरोह में कई बड़े मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के छात्र शामिल थे। पुलिस ने बीएचयू नर्सिंग की छात्रा पूनम कुमारी को दूसरे अभ्यर्थी के नाम पर परीक्षा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके अलावा, एम्स रायबरेली के छात्र सौरभ झा, दिल्ली के शाहदरा स्थित मेडिकल कॉलेज के इंटर्न अमन अग्रवाल और एनएमसीएच नर्सिंग के छात्र संजीत व उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। यह सामने आया है कि नीट परीक्षा के दौरान मेडिकल छात्रों को अपने कैंपस से बाहर न जाने के सख्त निर्देश दिए गए थे।

कांगो में इबोला संकट गहराया, 1,000 से अधिक लोग संक्रमित, मृतकों की संख्या 254 पहुंची

किंशासा। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (डीआरसी) में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गयी है और इस वायरस के संक्रमण से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 254 पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

डीआरसी (कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य) के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में इबोला संक्रमण के 1,003 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमण से मृत्यु दर (केस फेटेलिटी रेट) 25.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार कुल 365 मरीज वर्तमान में आइसोलेशन में या अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 100 मरीज ठीक हो चुके हैं। तीन प्रभावित प्रांतों में मरीजों के संपर्क में आये लोगों की निगरानी दर 58 प्रतिशत रही। अधिकारियों ने कहा कि मामलों में वृद्धि के बावजूद इबोला से निपटने के प्रयास सक्रिय हैं। इसके तहत निगरानी बढ़ायी गयी है। सामुदायिक संपर्क तेज किया गया है और मामलों के प्रबंधन तथा जांच क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

1971 युद्ध में आईएनएस राजपूत की भूमिका को हमेशा रखा जाएगा याद

नई दिल्ली। साल 1971 की भारत-पाकिस्तार वार में पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण पनडुब्बी, पीएनएस गाजी, समुद्र की गहराइयों में समा गई और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान से पानी के नीचे का खतरा लगभग समाप्त हो गया। इस ऐतिहासिक घटना में भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस राजपूत की भूमिका को हमेशा याद किया जाता है। आईएनएस राजपूत, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए एचएमएस रॉदरहैम के रूप में बनाया गया था, भारतीय नौसेना के शुरूआती और सबसे अनुभवी विध्वंसक युद्धपोतों में से एक था। इसे 1949 में भारत को सौंपा गया और इसका नाम आईएनएस राजपूत रखा गया। यह युद्धपोत लगभग तीन दशकों तक भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद 1979 में सेवानिवृत्त कर दिया गया। 3 दिसंबर 1971 की सुबह विशाखापत्तनम के तट पर एक सामान्य दिन की तरह हुई थी, लेकिन उसी रात और 4 दिसंबर की शुरूआती घंटों में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत-पाकिस्तान युद्ध की दिशा बदल दी।

यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, रिकार्ड पर पहुंचा तापमान

ब्रुसेल्स. यूरोप के कई देश इस समय खतरनाक गर्मी की चपेट में हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जगह यह रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि फ्रांस ने कुछ इलाकों में शराब के सेवन और बिक्री पर आंशिक रोक लगा दी है। वहीं जर्मनी में देशभर में गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की गई है और स्पेन में एक बड़ा फुटबॉल फैन जोन बंद करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस, पेरिस और बगंडी क्षेत्रों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ जगहों पर पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। सरकार लोगों से घर के अंदर रहने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की अपील कर रही है। इटली में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। राजधानी रोम में ऐतिहासिक कोलोसियम देखने आने वाले पर्यटक तेज धूप में परेशान नजर आए। कई लोग राहत पाने के लिए प्राचीन क्लॉडियस मंदिर के अंडरग्राउंड हिस्सों में पहुंचे, जहां तापमान अपेक्षाकृत कम था। उत्तरी इटली के शहर बोलोग्ना में भी लोग गर्मी से बचने के लिए फव्वारों पर पानी से चेहरा धोते और इमारतों की छाया में बैठते दिखाई दिए। यह शहर इटली के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है।

स्पेन में फुटबॉल फैन जोन बंद

स्पेन में गर्मी के कारण फुटबॉल महासंघ ने मैड्रिड के प्लाजा डी कोलोन में बनाया गया फैन जोन बंद कर दिया है। यहां विशाल स्क्रीन पर स्पेन और सऊदी अरब के बीच होने वाला वर्ल्ड कप मैच दिखाया जाना था। अब प्रशंसकों को मैच दूसरी जगहों पर देखना होगा. हालांकि खिलाड़ियों को अमेरिका के अटलांटा स्थित एयर-कंडीशंड स्टेडियम में खेलने की सुविधा मिलेगी, जो आंशिक रूप से सौर ऊर्जा से चलता है।

मैदानों में प्रचंड गर्मी, पहाड़ों में सैलानियों का सैलाब

चंडीगढ़-मनाली एनएच पर ट्रैफिक का भार, 5.25 लाख वाहन गुजरे

मंडी. चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह एचएच पांच लाख से ज्यादा वाहनों का दबाव झेल रहा है। एक महीने में नेशनल हाइवे से होते हुए 5.25 लाख से अधिक वाहन गुजरे हैं। इन वाहनों में कुल्लू-मनाली जाने वालों की संख्या अधिक है। वहीं, मंडी से लेकर औट तक पांच स्थानों पर आपदा के जख्त अभी भी हरे हैं।

यह पांच स्पॉट वन-वे हैं, जो जाम की बड़ी वजह हैं। आंकड़ों के अनुसार 22 मई से 21 जून तक मंडी से होकर पांच लाख 25 हजार 684 वाहन गुजरे हैं, जिससे हाईवे पर यातायात का भारी दबाव बना हुआ है। इनमें दो लाख 68 हजार 798 वाहन कुल्लू-मनाली की ओर रवाना हुए, जबकि दो लाख 57 हजार 66 वाहन चंडीगढ़ की दिशा में गए।

बड़ी संख्या में पर्यटकों के हिमाचल पहुंचने से हाईवे के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित हुई है। आपदा से प्रभावित यह राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी कई स्थानों पर पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है, जिससे यात्रियों को बार-बार जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के कारण कुछ स्थानों पर यातायात की गति और भी धीमी हुई है।

मंडी के झलोगी टनल क्षेत्र से लेकर औट तक ऐसे पांच संवेदनशील स्थान हैं, जहां पिछले आपदा के दौरान पहाड़ दरकने से मलबा सडक तक आ गया था। इन स्थानों पर अभी भी सडक पूरी चौड़ाई में बहाल नहीं हो सकी है। सुरक्षा कारणों से इन जगहों पर वाहनों को वन-वे प्रणाली के तहत निकाला जाता है। एक समय में केवल एक दिशा के वाहनों को गुजरने की अनुमति मिलने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जो जाम का प्रमुख कारण बन रही हैं।

30 जवान दिन-रात संभाल रहे यातायात व्यवस्था

एसपी मंडी विनोद कुमार ने बताया कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए मंडी पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। मंडी से औट तक हाईवे पर करीब 30 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। ये जवान दिन और रात की शिफ्टों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने और जाम की स्थिति से निपटने के लिए लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक कम है। इससे पहले कुल्लू-मनाली की ओर जाने वाले पर्यटकों की संख्या ज्यादा थी।

शिमला में दो महीने में 16 लाख से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही

शिमला. ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के दौरान लाखों पर्यटकों की आमद के बीच शिमला पुलिस ने उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन का नया मानक स्थापित किया है।

मई और जून के दौरान जिला शिमला के विभिन्न प्रवेश मार्गों से 16 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है। इनमें मई माह में लगभग 8.5 लाख तथा जून माह में अब तक करीब 7.5 लाख वाहन जिले में प्रवेश कर चुके हैं। पर्यटन सीजन को देखते हुए शिमला पुलिस ने यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या 136 से बढ़ाकर 220 कर दी है।

इसके अलावा करीब 50 सिविल वालंटियर्स और छात्र स्वयंसेवक भी ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं। वहीं, ट्रैफिक बाइक राइडर्स की संख्या सात से बढ़ाकर 32 कर दी गई है, जो संवेदनशील स्थानों पर तत्काल पहुंचकर यातायात बहाली सुनिश्चित कर रहे हैं। शिमला पुलिस द्वारा कुफरी, मशोबरा, नारकंडा, हाटू और अपर शिमला तथा किन्नौर की ओर जाने वाले वाहनों को शोगी-मेहली बाईपास मार्ग के उपयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 800 वाहनों को इस वैकल्पिक मार्ग की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।

पांच सेक्टरों में बंटा शहर

बेहतर निगरानी और प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरे शहर को पांच सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक ग्रेड-वन अधिकारी को सौंपी गई है। वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

ताजा खबर

संक्षिप्त

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोकभवन में किया योगाभ्यास

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। योगाभ्यास में राज्य की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे, उप सचिव सुश्री निधि साहू सहित लोकभवन के अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। ईशा फाउंडेशन के योग प्रशिक्षक श्री रितेश प्रधान ने योग नमस्कार का अभ्यास कराया। वहीं योग आयोग के प्रशिक्षक श्री भोजराज साहू, श्री अशोक साहू, श्री धनश्री साहू, श्री दीनू राम साहू एवं श्री तुषार साहू ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया।

मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए जीवन को संतुलित करने का सशक्त माध्यम है योग-कुलपति प्रो. मनोज दयाल

रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने किया। इस अवसर पर शासकीय मिडिल स्कूल, काठाडीह की प्रभारी प्रधान पाठिका ने मुख्य योग प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं को योग प्रोटोकॉल के अनुरूप योगाभ्यास कराया। कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में हजारों वर्ष प्राचीन योगसूत्रों को महर्षि पतंजलि ने सूत्रबद्ध और सुव्यवस्थित किया था। आज के दौर में हमें योग विज्ञान के व्यावहारिक महत्व के साथ-साथ इसके व्यावसायिक उद्यम के उभरते स्वरूप को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मीडिया शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षार्थियों, शोधार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए योग बेहद जरूरी है। इसके नियमित अभ्यास से वे अपने चुनौतीपूर्ण जीवन को संतुलित एवं संयमित करते हुए अपने भीतर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रोज करें योग : अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आज दुर्ग जिला मुख्यालय में खालसा पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्री विजय बघेल, विधायक रिकेश सेन, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाण्डेय, पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती उषा बारले, महापौर श्रीमती अलका बाघमार, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे, संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, आईजी श्री अभिषेक सांडिल्य, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, एसएसपी श्री विजय अग्रवाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष संपूर्ण देश में ''योगा फॉर हेल्दी एजिंग'' के लिए योग दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने सभी से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग का जीवन में बड़ा महत्व है। योग ऐसा सशक्त माध्यम है, जिससे शारीरिक एवं बौद्धिक विकास संभव है।

सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केन्द्र - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज यहां राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रमुख केन्द्र है। सोमनाथ मंदिर को अनेक बार आक्रांताओं ने तोड़ा, लेकिन हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, ये देशवासियों की अटूट आस्था का परिणाम है।

सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन से छत्तीसगढ़ से सोमनाथ के लिए 1000 से अधिक विशिष्टजन, पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार रवाना हुए। यात्रा में शामिल श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के शिवालयों की पावन भूमि के माटी कलश और पावन नदियों का जल कलश बाबा सोमनाथ को अर्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान सोमनाथ से छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवशाली दिन है जब प्रदेश भर से 1000 से अधिक श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में

11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राष्ट्रीय स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व के अंतर्गत सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उन्होंने भारत की आजादी के बाद राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। 75 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद जी ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से पद्मश्री, राज्य एवं राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित कलाकार एवं साहित्यकार इस यात्रा में अपने साथ अपने-अपने क्षेत्रों के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के शिवालयों की पावन माटी और पावन नदियों के जल कलश लेकर रवाना हो रहे हैं। यह यात्रा भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण है।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सोमनाथ धाम की यह यात्रा श्रद्धालुओं को केवल आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं बल्कि भारत की महान सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय गौरव को निकट से अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करेगी। भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित भारतवर्ष को समृद्धि, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्हें अंगवस्त्र भेंट किया।

सहकारी आवासीय सोसायटी निवासियों को मिली राहत

प्रमोटर को सिंकिंग फण्ड और कॉमन एरिया आवासीय सोसायटी को सौंपने के सख्त निर्देश

रायपुर ।छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने गृह क्रेताओं (होम बायर्स) के हितों की रक्षा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेरा ने दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में स्थित पंजीकृत आवासीय परियोजना %हर्षित नियोज सिटी% से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में निवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने परियोजना के प्रमोटर को सिंकिंग फंड की पूरी राशि और कॉमन एरिया का प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सहकारी आवासीय सोसायटी को हस्तांतरित करने का सख्त निर्देश दिया है।इस आदेश के बाद हर्षित नियोज सिटी के निवासियों और उनकी सहकारी समिति को लंबे समय से चल रहे विवाद से बड़ी राहत मिली है।

प्रमोटर की मनमानी पर लगी रोक

यह पूरा मामला तब सामने आया जब %हर्षित नियोज सिटी रेसिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित% ने परियोजना के प्रमोटर सिंघनिया बिल्डॉन प्रा.लि. एवं मेसर्स हर्षित सिंघानिया बिल्डॉन के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी। सोसायटी ने अपनी शिकायत में गंभीर मुद्दे उठाए थे, परियोजना की रखरखाव (मैंटेनेंस) व्यवस्था में कमियां, साझा सुविधाओं के संचालन में अनियमितता, सिंकिंग फंड की राशि का ट्रांसफर न होना, साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) को सोसायटी के सुपुर्द न किया जाना शामिल है।

सिंकिंग फंड और कॉमन एरिया पर रेरा का कड़ा रुख

मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ रेरा (छ्त्त्रक्ष्त्र) ने प्रमोटर की जवाबदेही तय करते हुए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने आदेश दिया है कि प्रमोटर द्वारा फ्लैट/इकाईधारकों से संकलित की गई सिंकिंग फंड की संपूर्ण राशि को नियमानुसार तुरंत सोसायटी के खाते में ट्रांसफर किया जाए। रेरा ने स्पष्ट किया कि यह निधि परिसर के दीर्घकालिक रखरखाव, मरम्मत और संरचनात्मक संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर सिर्फ निवासियों का हक है।

कॉमन एरिया पर मालिकाना हक सोसायटी का

रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 17 का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने सभी साझा क्षेत्रों (कॉमन एरिया) और उससे जुड़े अधिकारों को विधिवत सोसायटी के पक्ष में ट्रांसफर करने को कहा है। कानून के मुताबिक, प्रोजेक्ट पूरा होते ही कॉमन एरिया का स्वामित्व आवंटियों के संघ या सोसायटी को सौंपना बिल्डर का वैधानिक दायित्व है।

वास्तविक हितधारकों को मिलेगा नियंत्रण

CGRERA ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि साझा परिसंपत्तियों और संचित निधियों के ट्रांसफर में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समयबद्ध हस्तांतरण से अब परियोजना के वास्तविक हितधारकों (निवासियों) को अपने परिसर के रखरखाव और संचालन संबंधी फैसलों में पूरा अधिकार और नियंत्रण हासिल होगा।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बलौदाबाजार में किया योग

बलौदाबाजार। 12 वें अंतर्राष्टीय योग दिवस के अवसर पर रविवार 21 जून को जून को जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर बलौदाबाजार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल,विशिष्ट अतिथियों,अधिकारी -कर्मचारी एवं स्कूली बच्चों की उपस्थिति में ''स्वस्थ्य आयु के लिए योग'' आधारित थीम पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर सांसद अग्रवाल ने स्वस्थ शरीर व नशामुक्ति की शपथ दिलाई ।

सांसद अग्रवाल ने अंतर्राष्टीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा क़ि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज विश्व के लगभग 177 देश के कोने कोने में योगाभ्यास किया जा रहा है।योग भारत की प्राचीन जीवन पद्धति है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाहित है। योग ने केवल शारीरिक व मानसिक स्वस्थ को संतुलित करने का माध्यम है बल्कि जीवन में खुशहाली व समृद्धि भी लाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चे और युवा फ़ास्ट फ़ूड में ज्यादा रूचि लेते हैं,जिम जाते हैं। इस खान-पान से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता हैं। उन्होंने कहा क़ि सभी अधिकारी - कर्मचारी और विद्यार्थी योग को अपने दिनचर्या में शामिल करें,योग हमें निरोग और ख़ुशी प्रदान करता है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा क़ि योग हमारा अमूल्य धरोहर है। योग से तन -मन स्वस्थ होने के साथ ही अनुशासन और संयम सिखाता है। जीवन में शांति और समृद्धि के लिये ये सभी जरुरी है। योग को डेली रूटीन में अवश्य शामिल करना चाहिए।

कोटा नगर पंचायत को दिया नगर पालिका का दर्जा, विकास कार्यों में आएगी तेजी

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद बिलासपुर जिले के कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। नगर पालिका बनने से कोटा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

जनभावनाओं और वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि, 14 अगस्त 2025 को जनभावना के अनुरूप नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। और अब कोटा को नगर पालिका का दर्जा देकर वादा पूरा किया है। कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नगर पालिका बनने से नगर के विकास कार्यों में तेजी आएगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वैधानिक गठन और जनसांख्यिकीय आंकड़े

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगर पालिका कोटा का गठन किया है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा का क्षेत्र ही नगर पालिका कोटा की सीमा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 है।

स्थानीय नागरिकों में हर्ष की लहर

वहीं सरकार के इस निर्णय का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेसीआई रायपुर संस्कार एवं योग भारती संस्थान का संयुक्त आयोजन संपन्न

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेसीआई रायपुर संस्कार (ज़ोन-27) एवं योग भारती संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं योग साधकों ने सहभागिता कर योगाभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान सत्रों का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत योग प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान भी किया गया।

इस अवसर पर जेसीआई रायपुर संस्कार की अध्यक्ष जेसी बरखा अंडानी एवं सचिव जेसी अंकित दास मानिकपुरी द्वारा योग भारती संस्थान के संस्थापक एवं योग गुरु शंभू गुप्ता का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान उनके द्वारा वर्षों से योग के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने एवं लोगों को निरोग जीवन की प्रेरणा देने के कार्यों की सराहना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्षा जेसी बरखा अंडानी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का सशक्त माध्यम है। योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाकर हम एक स्वस्थ एवं सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। अध्याय समन्वयक JFM JCJ Sen Nilesh Shah एवं अध्याय प्रभारी JC HGF CA Sagar Jain ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो व्यक्ति को संतुलित एवं स्वस्थ बनाती अध्याय के सचिव जेसी अंकित दास मानिकपुरी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भले ही वर्ष में एक बार मनाया जाता है, लेकिन यदि योग को हम अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लें तो अनेक रोगों से दूर रह सकते हैं तथा निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मन को शांत, बुद्धि को प्रखर एवं व्यक्तित्व को संतुलित बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से मन, मस्तिष्क और शरीर का समग्र विकास संभव है तथा एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में IPP जेसी आदित्य सिंह टिकरिया, जेसीआई रायपुर संस्कार के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों, योग भारती संस्थान के प्रशिक्षकों एवं स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा।

अंत में सभी उपस्थितजनों ने Yoga for One Earth, One Health" की भावना के अनुरूप नियमित योग करने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने एवं योग के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम बताया

33 जेलों में उत्साहपूर्वक मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी 33 जेलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्सवपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जेल, रायपुर में मुख्य अतिथि के रूप में जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से आज पूरा विश्व योग के रंग में रंगा हुआ है। हम सभी इस महान भारतीय परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। वास्तव में योग का अर्थ अपने शरीर को अपने मन से जोड़ना, अपनी सांसों को अपनी आत्मा से जोड़ना, और खुद को एक सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ना है।

गुप्ता ने कहा कि योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का एक माध्यम है। यह तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। केन्द्रीय जेल रायपुर में विशेष योग शिविर का आयोजन भव्य रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय जेल रायपुर के पुरूष प्रकोष्ठ में 500 बंदियों ने एवं महिला प्रकोष्ठ में 150 महिला बंदियों ने भाग लिया। योग सत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के अनुभवी योग प्रशिक्षण अनिल अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न योग आसनों, प्राणयाम तथा ध्यान की तकनीकों का अभ्यास कराया गया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य बंदियों को मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार, अवसाद जैसी समस्यों से मुक्ति दिला कर उनमें आत्माविश्वास, संयम, आत्म-नियंत्रण एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था। योग शिविर में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पवनमुक्तासन, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ध्यान आदि कियाओं को अभ्यास कराया गया। योग प्रशिक्षकों द्वारा इन योगासनों के मानसिक एवं शारीरिक लाभ को बताया गया। इस अवसर पर योगेश सिंह क्षत्री (जेल अधीक्षक) एवं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक भी उपस्थित थे।

योग दिवस कार्यक्रम में प्रशासन की लापरवाही

पोस्टर में फोटो नहीं लगाने से नाराज विधायक उठे मंच से

बेमेतरा। बेमेतरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई, जब साजा विधायक ईश्वर साहू कार्यक्रम के पोस्टर में अपना फोटो नहीं होने पर नाराज होकर मंच से उठ गए। स्थिति को बिगड़ते देख अधिकारी विधायक का मान-मनौव्वल करने लगे, जिसके बाद विधायक मंच पर लौटे।

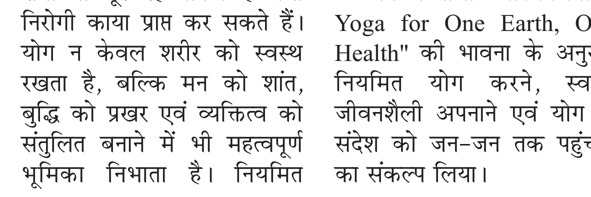

जानकारी के अनुसार, बेमेतरा जिले में तीन विधानसभा क्षेत्र-बेमेतरा, नवागढ़ और साजा आते हैं। योग दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और साजा विधायक ईश्वर साहू के साथ जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

कार्यक्रम के लिए स्थल पर लगाए गए पोस्टर में बेमेतरा और नवागढ़ क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों के फोटो तो शामिल किए गए, लेकिन साजा विधायक ईश्वर साहू का फोटो नहीं लगाया गया। इसी बात को लेकर विधायक नाराज हो गए और कार्यक्रम के दौरान मंच से उठकर चले गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और विधायक ईश्वर साहू को मनाया।

काफी समझाइश के बाद वे दोबारा मंच पर लौटे और कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यशैली, प्रोटोकॉल और जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा छेड़ दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे सरकारी और सार्वजनिक महत्व के कार्यक्रम में इस तरह की चूक को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है।

फीफा विश्व कप 2026 में गुलाबी जूतों का चलन बढ़ा

न्यूयॉर्क। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेले जा रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल में स्टार खिलाड़ी अपने अलग ही अंदाज में दिखते है। इस बार अधिकतर स्टार खिलाड़ी गुलाबी जूते पहनकर खेलते दिख रहे हैं। इस कारण विश्वकप कप में गुलाबी जूते पहने खिलाड़ी छाये हुए हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उन्हें पसंद कर रहे हैं।

अमेरिका के युवा फुटबॉलर जियो रेना ने टूनार्मेंट के शुरूआती मैच में ही गुलाबी जूतों में एक यादगार गोल दागकर अपना प्रभाव दिखाया है। वहीं ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर भी अपने पहले ही मुकाबले में ध्यान खींचा, उनके पैरों में भी चमकीले गुलाबी पहनकर मैदान में छाये हुए थे। वहीं फ्रांस के स्टार खिलाड़ किलियान एमबाप्पे ने भी दो गोल दागने के दौरान गुलाबी जूते ही पहने थे। इसके अलावा इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने भी दो गोल लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की और वह भी गुलाबी जूतों में ही नजर

आये थे।

मैदान गुलाबी जूते पहने खिलाड़ी दूर से ही अलग नजर आ जाते हैं। यही कारण है कि इस रंग के जूते पहने खिलाड़ी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यही वजह है कि कई बड़ी स्पोर्ट्स कंपनियों ने भी इनके विशेष डिजाइन तैयार किए हैं। नाइकी के ग्लोबल फुटवियर निदेशक, ओडिंगा निमाको के अनुसार, यह रंग सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि खिलाड़ी इसे आत्मविश्वास, ऊर्जा और अपनी व्यक्तिगत पहचान के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दर्शकों के बीच भी यह रंग तेजी से छा रहा है।

साल 1998 के विश्व कप में पहली बार रंगीन फुटबॉल जूतों का चलन शुरू हुआ था। उससे पहले तक काले और सफेद रंग के जूते ही पहने जाते में थे। वहीं अब नाइकी, एडीडास, प्यूमा, स्केचर्स और न्यू बैलेंस जैसी दुनिया की दिग्गज खेल निर्मात कंपनियाँ भी बड़े स्तर पर गुलाबी रंग के जूतों को बाजार में उतार चुकी हैं।

शाहिदी एक विशेष क्लब का हिस्सा बने

चेन्नई। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी अपने एकदिवसीय करियर में 13 साल के बाद पहला शतक लगाने के साथ ही दिग्गज क्रिकेटरों के खास क्लब का हिस्सा बन गये हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारी दबाव के बीच ही एक दशक से भी अधिक समय तक अपने को लगातार साबित करते रहना और अपने पहले शतक के लिए इतने लंबे इंतजार के बाद सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है पर शहिदी निराश नहीं हुए। इसी कारण वह भारत के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय में 102 रनों की यादगार पारी खेलने में सफल रहे।

साल 2013 में अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में कदम रखने वाले शाहिदी को अपने पहले शतक तक पहुंचने में पूरे 4644 दिन का अविश्वसनीय रूप से लंबा सफर तय करना पड़ा। यह यात्रा इतनी लंबी और संघर्षपूर्ण थी कि इसने क्रिकेट प्रेमियों को गुजरे दौर के उन महान बल्लेबाजों की याद दिला दी जिन्होंने भी अपने करियर में ऐसे ही किसी खास मुकाम के लिए लंबा इंतजार किया था। एकदिवसीयच डेब्यू से लेकर पहले शतक के बीच सबसे ज्यादा दिनों के इंतजार के मामले में, शाहिदी अब दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, और इस सूची में उनका नाम जुड़ना उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प को दिखाता है। इस ऐतिहासिक और बेहद खास क्लब में सबसे ऊपर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रेगिस चकाबवा हैं, जिन्हें अपने पहले एकदिवसीय शतक के लिए 5040 दिनों का एक अकल्पनीय लंबा इंतजार करना पड़ा था। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक, सुनील गावस्कर का नाम आता है। गावस्कर ने अपने पहले एकदिवीसय शतक के लिए 4858 दिनों का लंबा समय लिया था, जो उनकी एकदिवसीय करियर की शुरूआत के काफी बाद आया। इसके ठीक बाद श्रीलंका को विश्व विजेता बनाने वाले पूर्व कप्तान अर्जुन राणातुंगा का नंबर आता है, जिन्होंने 4674 दिनों के बाद अपनी पहली वनडे सेंचुरी बनाई थी। अब हशमतुल्लाह शाहिदी 4644 दिनों के इंतजार के बाद इस अत्यंत विशिष्ट और ऐतिहासिक एलीट क्लब के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। उनके ठीक पीछे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन हैं, जिन्होंने अपने पहले शतक के लिए 4639 दिन लिए थे।

मनिका ने एशियाई खेलों के लिए टीम चयन की प्रकिया पर उठाये सवाल

नई। भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा 2026 एशियाई खेलों के लिए टीम में जगह नहीं मिलने के बाद से ही निराशा हैं। मनिका ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें

अधिक पारदर्शिता होनी चाहिये है।आइची-नागोया एशियाई खेलों के लिए 10 सदस्यों की भारतीय टीम में मनिका जगह की प्रबल दावेदार थी पर जिस प्रकार से उन्हें बाहर रखा गया है उससे प्रशंसक भी हैरान हैं। मनिका को केवल रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में जगह मिली है। इस ओलंपियन ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एशियाई खेल 2026 की टीम में चयन नहीं होने से वह हैरान है। इसके लिए उन्हें कोई तर्कसंगत कारण भी नहीं बताया गया है। उन्होंने चयन मापदंडों में विसंगति की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रदर्शन में निरंतरता को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि मेरे मामले में पिछले चयन चक्र के मुकाबले अलग-अलग पैमाने और बातों को ध्यान में रखा गया है। अगर वही नियम लागू होने थे जो पिछले एशियाई खेलों के चयन में लागू हुए थे, तो स्थिति अलग होती। उन्होंने खेल मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ से अनुरोध किया कि वे इस मामले का संज्ञान लें और चयन के नियमों को पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से लागू करना सुनिश्चित करें।

ग्रुप सी के अंतिम मैच से वापसी करेंगे नेमार : एंसेलोटी

न्यूयार्क। ब्राजील की फुटबॉल टीम के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने कहा है कि स्टार खिलाड़ी नेमार विश्वकप में वापसी के लिए तैयार हैं। एंसेलोटी के अनुसार स्टार फॉरवर्ड नेमार स्कॉटलैंड के खिलाफ 24 जून को होने वाले ग्रुप सी के अंतिम और निर्णायक मैच के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगे। नेमार की विश्व कप में वापसी की घोषणा से उनके प्रशंसक उत्साहित हैं। नेमार की वापसी निश्चित रूप से पांच बार की विजेत टीम के मनोबल और आक्रमण शक्ति को एक अभूतपूर्व बढ़ावा देगी, जो आगामी मैचों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। टीम को अब अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा, जिससे विरोधी टीमों के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी।

गौरतलब है कि नेमार, ब्राजील की शीर्ष लीग में सैंटोस के लिए खेलते हैं और पिंडली में खिंचाव के कारण 17 मई से ही खेल के मैदान से दूर थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण चोट के चलते वह टूनार्मेंट के शुरूआती दो अहम मैचों में शामिल नहीं हो पाए थे, जिनमें मोरक्को के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ हुआ मैच और हाल ही में हैती के खिलाफ मिली जीत भी शामिल है। उनके बाहर होने से टीम का मनोबल घटा है जो मुकाबलों के दौरान देखने में आया है। ऐसे में उनकी वापसी को लेकर प्रशंसक जोश से भरे हुए हैं। इसका कारण है कि नेमार के रहने से टीम प्रेरित होती है।

हालांकि, पिछले कुछ दिनों से नेमार अपनी पूरी फि टनेस हासिल करने में लगे थे। इसी कारण वह न्यू जर्सी के मॉरिसटाउन में पूरी ट्रेनिंग किट में नजर आए और अपने साथियों के साथ अभ्यास में शामिल हुए। दिग्गज खिलाड़ी ने कोचिंग स्टाफ के साथ अलग से काम करने से पहले राफिन्या, ब्रूनो गुइमारेस, गैब्रियल मैगलहेस और फैबिन्हो जैसे अपने प्रमुख साथियों के साथ टीम की एक्सरसाइज में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। यह सब उनकी वापसी के स्पष्ट संकेत थे।वहीं मैनेजर एंसेलोटी ने ही सबसे स्पष्ट और निर्णायक संकेत दिया था कि नेमार की वापसी अब बस कुछ ही दूरी पर है। उनकी इस घोषणा ने अटकलों पर विराम लगा दिया है और अब ब्राजील की पूरी टीम और समर्थक एक बार फिर नेमार के खेल का जादू देखने को उत्सुक हैं। नेमार की मैदान पर वापसी न केवल ब्राजील की आक्रमण पंक्ति को और धार देगी, बल्कि विपक्षी टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश करेगी।।

रोहित के आलोचकों पर बरसे कैफ, ऐसे लोग चाहते हैं वह विफल हो जाएं

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को असफल होने देखना चाहते हैं जिससे कि उन्हें एकदिवसीय विश्वकप से बाहर करने का अवसर मिल जाये।

कैफ के अनुसार रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंतिम एकदिवसीय मैच में 79 रनों की पारी खेलकर साबित कर दिया है कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बचा है और वह बड़े स्कोर बनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। इसी कारण वह 39 साल की उम्र में भी जमकर रन बना रहे हैं। इस प्रकार जहां एक ओर रोहित अगले साल होने वाल एकदिवसीय विश्वप कप के लिए अपनी दावेदारी पक्की कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे आलोचक भी हैं जो उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उन्हें रोकना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं चाहते कि रोहित विश्वकप खेलें। साथ ही कहा कि ऐसे लोगा चाहते हैं कि रोहित असफल हो जाएं जिससे उन्हें बाहर करने का अवसर मिल जाये।

वहीं रोहित ने अपनी पिछली 10 पारियों में एक शतक, दो बार 75 या उससे अधिक रन, एक 57 रनों की पारी और एक 48 रनों की पारी खेली है, जो उनकी बेहतरीन लय को दिखाती है जबकि आलोचक एक पारी में विफल होने पर ही इनके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर

देते हैं। कैफ ने कहा कि चयन का पैमान उम्र नहीं, बल्कि फॉर्म होनी चाहिए। विशेष रुप से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के मामले में। ये दोनों ही खिलाड़ी अब टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और केवल एकदिवसीय क्रिकेट ही खेल रहे हैं।

कैफ ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, सच में समझ नहीं आता कि इतने सारे लोग क्यों चाहते हैं कि रोहित विफल हो जाएं। उन्होंने जिस तरह से विपरीत हालातों का सामना किया है, वह प्रशांसा के योग्य है। कैफ ने रोहित की पिछली उपलब्धियों को भी याद दिलाया, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाना और अब अफगानिस्तान के खिलाफ 79 रनों की पारी शामिल है। उनका मानना है कि एक दो छोटे स्कोर को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका समय पूरा हो गय है। कैफ ने क्रिकेट प्रशंसकों से अपील की कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि रोहित 2027 एकदिवसीय विश्वकप में भी अपने फॉर्म को बनाये रखें, गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भी उनकी फॉर्म और फिटनेस पर सवाल उठे थे पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलायी। इसके बाद भी हैरानी की बात है कि उन्हें कप्तानी से बाहर कर दिया गया। वहीं अब कहा जा रहा टीम में भी उन्हें नहीं रखा जाना चाहिये। इसके बाद भी रोहित ने सभी प्रकार के दबावों को पीछे छोड़ते हुए फिटनेस बनाने के साथ ही प्रदर्शन को भी बेहतर कर विश्वकप के लिए मजबूत दावेदारी की है।

कारोबार

भू-राजनीति, मानसून और आर्थिक आंकड़े तय करेंगे बाजार की दिशा

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार पिछले सप्ताह की गिरावट से उबरने की कोशिश में इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू कारकों पर पैनी नजर रखेंगे।

निवेशकों के लिए जहां भू-राजनीतिक स्थिरता अहम होगी, वहीं देश के भीतर मानसून की प्रगति और प्रमुख आर्थिक आंकड़े भी बाजार की दिशा तय करेंगे। विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के क्रियान्वयन में होने वाली प्रगति पर बाजार की गहरी निगाहें टिकी रहेंगी। यदि

हॉर्मुज जलडमरूमध्य व्यापार के लिए सुचारु रूप से खुलता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और भू-राजनीतिक स्थिरता पर इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा, जो शेयर बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकता है। वैश्विक परिदृश्य के साथ ही घरेलू मोर्चे पर मानसून की प्रगति भी निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

कृषि-आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर मानसून ग्रामीण मांग और कॉर्पोरेट आय को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, देश के आठ महत्वपूर्ण कोर उद्योगों के आंकड़े भी जारी होंगे, जो अर्थव्यवस्था की सेहत का संकेत देंगे और बाजार की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी कारकों का समग्र प्रभाव आगामी सप्ताह में बाजार की दिशा तय करेगा। बाजार के विश्लेषकों ने कहा कि बाजार की नजर मई महीने के थोक मूल्य सूचकांक (डब्लयूपीआई) और रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के मिनट्स पर टिकी हुई है, ताकि भविष्य की ब्याज दरों का अनुमान लगाया जा सके। विदेशी निवेशकों के रुख और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों से बाजार में तरलता तय हो रही है। पश्चिमएशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दामों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की धारणा पर पड़ सकता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे लुढ़कर 94.36 पर खुला

मुंबई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को भारतीय रुपया 94.36 पर खुला। यह पिछले बंद के स्तर से 4 पैसे कमजोर रहा। हालांकि, यह पिछले सप्ताह की मजबूती के बाद हुआ है, जब रुपये ने 0.8 फीसदी की शानदार वापसी की थी। यह लगभग 3 महीनों में उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। उस दौरान रुपया 94.18 के कई महीनों के उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया था और मई के रिकॉर्ड निचले स्तर 97 से संभल गया था।

घरेलू बाजार में सोना-चांदी उछले, विदेशी बाजार में भाव नरम

नई दिल्ली। घरेलू वायदा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नरमी का रुख बना रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना सुस्त शुरूआत के बाद तेजी से ऊपर चढ़ा, वहीं चांदी ने मजबूत शुरूआत के बाद अपनी चमक बरकरार रखी। खबर लिखे जाने तक सोने के वायदा भाव 1,47,650 रुपये और चांदी के भाव 2,34,950 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 2,093 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,110 रुपये के भाव पर खुला, जबकि इसका पिछला बंद भाव 1,47,203 रुपये था। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही इसमें जबरदस्त वापसी दिखी और खबर लिखे जाने तक यह 427 रुपये की तेजी के साथ 1,47,630 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस दौरान इसने 1,47,987 रुपये का उच्च स्तर और 1,45,110 रुपये का निम्न स्तर छुआ।

सोने का भाव 1,47,650 और चांदी 2,34,950 रुपए प्रति किलोग्राम

इस साल सोने ने 1,80,779 रुपये का सर्वोच्च स्तर भी देखा था। चांदी के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ने 3,903 रुपये की मजबूत तेजी के साथ 2,37,088 रुपये पर कारोबार शुरू किया, जबकि पिछला बंद भाव 2,33,185 रुपये था। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 1,791 रुपये की तेजी के साथ 2,34,976 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इसने 2,37,106 रुपये का दिन का उच्चतम और 2,34,908 रुपये का निम्नतम स्तर छुआ। चांदी का इस साल का सर्वोच्च स्तर 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोने के वायदा भाव में नरमी देखी गई। यह 4,231.20 डॉलर प्रति औंस पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 4,245.90 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने तक यह 38.40 डॉलर की गिरावट के साथ 4,207.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। सोने ने इस साल 5,586.20 डॉलर का सर्वोच्च स्तर छुआ है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव भी गिरावट के साथ 65.78 डॉलर प्रति औंस पर खुले, जो पिछले बंद भाव 66.31 डॉलर से कम था। खबर लिखे जाने के समय यह 0.63 डॉलर की गिरावट के साथ 65.68 डॉलर प्रति औंस पर था। चांदी का इस साल का उच्चतम स्तर 121.79 डॉलर रहा है।

स्टोरिया और इंग्लिश अवन पर भ्रामक दावों के लिए उपभोक्ता प्राधिकरण ने लगाया जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने खाद्य उत्पादों के संबंध में 100 प्रतिशत शब्द के भ्रामक इस्तेमाल और कारोबार में अनुचित तरीके अपनाने के लिए दो कंपनियों पर एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है।

नई दिल्ली

जिन कंपनियों पर जुमार्ना लगाया गया है उनमें स्टोरिया फूड्स एंड बेव्रिजेज प्राइवेट लिमिटेड और इंग्लिश अवन ब्रांड नाम से कारोबार करने वाली कंपनी बेक्टर्स फूड स्पेशियलिटीज लिमिटेड शामिल हैं।

प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उत्पादों की पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्मों से इन भ्रामक दावों को तत्काल हटायें। यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा भ्रामक विज्ञापनों और उनके समर्थन की रोकथाम संबंधी दिशा-निर्देश, 2022 के तहत की गयी है। सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लेते हुए स्टोरिया के 100 प्रतिशत नारियल पानी और 100 प्रतिशत अनार, मिक्स्ड फ्रूट, आम, तथा अमरूद और चिली जूसों की जांच की। इन उत्पादों का प्रचार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, उत्पाद पैकेजिंग तथा विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर किया गया था।

कंपनी ने पैकेजिंग और प्रचार में 100 प्रतिशत नारियल पानी लिख रखा था जबकि सामग्री के विवरण में पानी और नारियल पानी कॉन्सेंट्रेट (9.6 प्रतिशत) लिखा था। ब्रैकेट में लिखा था झ 100 प्रतिशत नारियल पानी के बराबर। सीसीपीए ने कहा कि एक सामान्य उपभोक्ता 100 प्रतिशत नारियल पानी का अर्थ पूरी तरह प्राकृतिक नारियल पानी समझेगा। उत्पाद में क्लास-2 संरक्षक आईएनएस 202 भी मौजूद था, इसलिए 100 प्रतिशत प्राकृतिक का दावा भी उचित नहीं था। इसी प्रकार कंपनी के 100 प्रतिशत अनार जूस में पानी, चार प्रतिशत अनार जूस का कॉन्सेंट्रेट और 10 प्रतिशत सेब से जूस का कॉन्सेंट्रेट पाया गया। उसके सभी जूस में पानी, उस फल का कॉन्सेंट्रेट और एप्पल जूस का कॉन्सेंट्रेट पाया गया।

बेकटर्स फूड स्पेशियरिटीज ने विभिन्न अखबारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर 100 प्रतिशत आटा ब्रेडह्व, 100 प्रतिशत होल ह्वीट ब्रेडह्व, टेस्ट ऑफ 100 पर्सेंट नरिशमेंट, फिल योर डेज विद 100 पर्सेंट, द टेस्ट ऑफ 100 पर्सेंट गुडनेस जैसे वाक्यांशों का प्रयोग किया था। इन वीडियो विज्ञापनों को 23 अप्रैल तक कुल मिलाकर 50 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था।

कार्यवाही के दौरान कंपनी ने स्वीकार किया कि उसके ब्रेड उत्पादों में केवल 87 प्रतिशत साबुत गेहूं का आटा था। सीसीपीए ने कहा है कि जिस उत्पाद में केवल 87 प्रतिशत साबुत गेहूं का आटा हो, उसे 100 प्रतिशत आटा ब्रेड या 100 प्रतिशत होल ह्वीट ब्रेड नहीं कहा जा सकता।

भोपाल जंक्शन का बदलेगा हुलिया

350 करोड़ से बनेगा भव्य स्टेशन, रेलवे बोर्ड को भेजे दस्तावेज

भोपाल। राजधानी के मुख्य रेल द्वार भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को जल्द ही एक नया और भव्य स्वरूप मिलने जा रहा है। रेलवे ने इस स्टेशन के कायाकल्प के लिए करीब 350 करोड़ रुपये के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भोपाल जंक्शन को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान देते हुए भव्य मंदिर शैली के अग्रभाग के साथ अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आधारित इस परियोजना के लिए टेंडर और बिड से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज फाइनल कर अंतिम मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिए गए हैं, जहां से हरी झंडी मिलते ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

रानी कमलापति के बाद दूसरा पीपीपी स्टेशन

इस बड़े बदलाव के बाद भोपाल जंक्शन शहर का ऐसा दूसरा रेलवे स्टेशन बन जाएगा, जिसे पीपीपी मॉडल के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। इससे पहले भोपाल के ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को इसी मॉडल पर विश्वस्तरीय बनाया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, इस नए प्रोजेक्ट के जरिए स्टेशन के मौजूदा बिल्ट-अप एरिया को 4,238 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 6,532 वर्ग मीटर किया जाएगा। इस बढ़े हुए दायरे से स्टेशन परिसर के भीतर यात्रियों को मिलने वाली सेवाओं और खाली स्पेस को बड़े पैमाने पर विस्तार देने में मदद मिलेगी।

यात्रियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

स्टेशन के भीतर आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर खाका तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों का सफर और सुगम हो सके।

परियोजना के प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार समझा जा सकता है:

- स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार को पारंपरिक और भव्य मंदिर कला की थीम पर डिजाइन किया जाएगा।
- यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित (AC) प्रतीक्षालय और बेहतर बैठने की व्यवस्था होगी।
- परिसर के भीतर आवागमन को आसान बनाने के लिए नए लिफ्ट और फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
- स्टेशन पर मौजूद प्रसाधनों को अपग्रेड कर विश्वस्तरीय और स्वच्छ बनाया जाएगा।
- बढ़े हुए निर्मित क्षेत्र के कारण यात्रियों को विभिन्न प्रकार की कमर्शियल सेवाएं भी स्टेशन के भीतर मिल सकेंगी।

मंजूरी मिलते ही शुरू होगा निर्माण

रेलवे प्रशासन का कहना है कि जैसे ही रेलवे बोर्ड से इस 350 करोड़ रुपये के बजट वाले प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस मिल जाएगा, निर्माण एजेंसियां जमीन पर काम शुरू कर देंगी। इस पुनर्विकास से न केवल भोपाल जंक्शन पर यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि भोपाल आने वाले पर्यटकों को स्टेशन से बाहर निकलते ही शहर की ऐतिहासिक और हेरिटेज पहचान की पहली झलक देखने को मिलेगी।

श्रुत पंचमी पर भव्य व्यंजन मेला एवं सम्मान समारोह का आयोजन

भोपाल। श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर महाकवि आचार्य ज्ञान सागर संस्कार केंद्र, अयोध्या नगर द्वारा अयोध्या नगर जैन मंदिर परिसर में भव्य व्यंजन मेला एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भोपाल की विभिन्न जैन पाठशालाओं का उत्साहपूर्ण सहभाग रहा।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अयोध्या नगर पाठशाला के संयोजक विवेक जैन एवंमनीष जैन मुगांवली ने बताया कि भोपाल के विभिन्न क्षेत्र की लगभग 15 जैन पाठशालाओं ने इस आयोजन में सहभागिता करते हुए 28 से अधिक आकर्षक एवं विविध व्यंजनों के स्टॉल लगाए। सभी पाठशालाओं के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं संचालकों, मंदिर समिति, महिला मंडल, जैन मिलन, जैन जागृति ग्रुप अयोध्या नगर ने भरपूर सहयोग प्रदान कर पूरे उत्साह, उमंग एवं समर्पण के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

व्यंजन मेले में पारंपरिक एवं लोकप्रिय व्यंजनों की विविधता ने आगंतुकों को आकर्षित किया। समाज के सैकड़ों लोगों ने परिवार सहित उपस्थित होकर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया तथा विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न पाठशालाओं के संचालकों, शिक्षकों एवं प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मनोरंजन एवं स्वाद का आनंद प्रदान करना ही नहीं था, बल्कि बच्चों में संगठन, सहयोग, संस्कार एवं सामाजिक सहभागिता की भावना को विकसित करना भी था।

आयोजकों ने बताया कि सभी पाठशालाओं ने अभूतपूर्व उत्साह एवं समर्पण के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। समाजजनों के सहयोग एवं सहभागिता से यह आयोजन अत्यंत सफल एवं यादगार रहा।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु से मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सौजन्य भेंट

भोपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से जबलपुर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की। इस गरिमामयी मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आत्मीय संवाद हुआ और संस्कृति व श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्हों का आदान-प्रदान किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश आगमन पर स्वागत करते हुए जीवनदायिनी मां नर्मदा की बेहद सुंदर प्रतिमा भेंट की। वहीं, राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने भी अपनी ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पुरी स्थित सुप्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की अलौकिक तस्वीर सप्रेम भेंट की। ओडिशा की ऐतिहासिक धरोहर कोणार्क सूर्य मंदिर के विश्व प्रसिद्ध चक्र की भव्य प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप प्रदान की।

अंबिकापुरी के खाटू श्याम धाम में पहली बार हो रही खाटू श्याम पर आधारित भागवत कथा

दिल्ली के आचार्य संजय प्रभाकर सुना रहे बाबा की गाथा, भक्तों में उत्साह

इंदौर। कलियुग के हारे का सहारा कहे जाने वाले खाटू श्याम बाबा की महिमा और उनके जीवन पर आधारित पांच दिवसीय खाटू श्याम भागवत कथा का आयोजन अंबिकापुरी स्थित खाटू श्याम धाम में किया जा रहा है। धाम के 29वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस अनूठे आयोजन में दिल्ली के आचार्य संजय प्रभाकर प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक भक्तों को श्याम बाबा की दिलचस्प गाथाएं सुना रहे हैं।

कथा के दौरान आचार्य प्रभाकर ने अब तक शिव विवाह, 24 अवतार, नागलोक, भीम-हिडिंबा विवाह एवं घटोत्कच के जन्म जैसे कई पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। रविवार को उन्होंने भक्त आलूसिंह, श्याम बहादुर, सोहनलाल लोहाकार और बर्बरीक के जन्म की कथा सुनाकर भक्तों को भावविभोर कर दिया। संतों ने बताया कि कलियुग में खाटू श्याम बाबा की जीवनी, उनकी शक्ति और सिद्धि के बारे में जानने के इच्छुक भक्तों के लिए यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। महंत नीलू बाबा ने बताया कि इस महोत्सव में महामंडलेश्वर गोपाल दास, राघवेंद्र दास, हनुमान दास, नलिनी दास, पंकज दास सहित अखाड़े के अनेक विद्वान संत उपस्थित रहे। कथा के पूर्व प्रतिदिन सुबह 8 से 11 बजे तक खाटू श्याम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संतों और भक्तों ने विश्व शांति एवं जन कल्याण की प्रार्थना की।

सोमवार को कथा में द्वारकाधीश-बर्बरीक संवाद, महिसागर संगम गुप्त तीर्थ, विजय सिद्धि महायज्ञ और लाल सिंदूरी भस्म की कथा सुनाई जाएगी। मंगलवार को पांडवों के वनवास और भीम-बर्बरीक के युद्ध के प्रसंग होंगे। बुधवार को कथा के समापन अवसर पर कुरुक्षेत्र में बर्बरीक का शक्ति प्रदर्शन, श्री कृष्ण द्वारा शीश दान और खाटू श्याम की महिमा का वर्णन किया जाएगा। व्यास पीठ का पूजन बाबूलाल कुमावत, रोशनलाल कुमावत, महेंद्र जांगिड़, जगदीश शर्मा और मनीष शर्मा द्वारा किया गया।

इंदौर में नीट परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से संपन्न

कलेक्टर ने केंद्रों का लिया जायजा

इंदौर। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा रविवार को शहर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, बैठने की सुविधा और अन्य आवश्यक इंतजामों का बारीकी से जायजा लिया।

कलेक्टर वर्मा ने एसजीएसआईटीएस और होलकर साइंस कॉलेज सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा कर फीडबैक लिया तथा किसी भी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

विशेष सुविधाएं रहीं उपलब्ध

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार भी साथ रहे। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। केंद्रों पर छाया, पेयजल और बैठने की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। साथ ही, उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री की उपलब्धता के साथ ही परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए बसों की विशेष व्यवस्था भी की गई थी, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में कोई असुविधा न हो।

शिवपुरी: जन चौपाल में गूंजे बिजली विभाग चोर है के नारे, मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार

वीरा गांव के ग्रामीणों का ऊर्जा मंत्री के सामने प्रदर्शन, टूटे तार न जोड़ने पर जताई नाराजगी

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के खोड़ स्थित धाय महादेव मंदिर परिसर में जन चौपाल में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जिले के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने वीरा गांव के ग्रामीणों ने बिजली विभाग चोर है के नारे लगाकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

अपने विभाग की समस्या सामने आकर ही चौंक गए मंत्री जी-

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लगभग दो घंटे तक जन चौपाल लगाई। इस दौरान बिजली, सड़क, सीमांकन, हैंडपंप और पेंशन से जुड़ी करीब 200 शिकायतें प्राप्त हुईं।

जन चौपाल में वीरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई बिजली के खंभे और तार टूटकर खेतों में पड़े हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने बारिश के मौसम में दुर्घटना की आशंका जताते हुए तत्काल समाधान की मांग की।

ग्रामीणों का कहना था कि लापरवाही के चलते किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।

तार जोड़ने के पैसे महंगे जाने का आरोप लगाया-

ग्रामीण सुखेंद्र राय ने आरोप लगाया कि शासकीय कार्य के लिए विभाग के कर्मचारियों ने उनके घर का तार काट दिया था। जोड़ने के लिए पहले पिता से 1500 रुपए लिए गए। अब 21 दिन से तार टूटा पड़ा है और दोबारा जोड़ने के लिए 3 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। इस तरह की वसूली से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

ऊर्जा मंत्री ने मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई-

ग्रामीणों की नाराजगी और आरोपों को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मौके पर मौजूद बिजली कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तत्काल समस्या के निराकरण के निर्देश दिए और कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे उन्हें प्रस्तुत की जाए। जन चौपाल से पहले मंत्री ने परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए। सांदीपनि विद्यालय गणेशखेड़ा की छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

गुना के डायल-112 हीरोज

कार दुर्घटना में घायल हुए 5 व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया

भोपाल। भोपाल, 21 जून 2026। गुना जिले के थाना आरोन क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्परता एवं साहसिक कार्रवाई से सड़क दुर्घटना में घायल 05 व्यक्तियों को सुरक्षित सहायता कर समय पर अस्पताल पहुँचाया गया। इस त्वरित कार्रवाई से घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

21 जून को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आरोन क्षेत्र अंतर्गत आरोनझराघौगढ़ मार्ग पर ग्राम शहरोक से आगे जंगल क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही आरोन थाना क्षेत्र में तैनात डायल 112 वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

डायल-112 स्टाफ सैनिक श्री शिवेंद्र रघुवंशी एवं पायलट श्री हेमराज भील ने मौके पर पहुँचकर पाया कि एक कार सड़क से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सवार 05 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डायल-112 जवानों ने तत्परता एवं साहस का परिचय देते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फँसे सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला तथा प्राथमिक सहायता प्रदान की। इसके बाद सभी घायलों को तत्काल डायल 112 वाहन से सिविल अस्पताल, आरोन पहुँचाया।

डायल-112 जवानों की त्वरित सहायता एवं मानवीय कार्यवाही से सभी घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकी। डायल-112 हीरोज श्रृंखला के अंतर्गत यह घटना दर्शाती है कि मध्यप्रदेश पुलिस की डायल-112 सेवा आपात परिस्थितियों में त्वरित राहत, बचाव एवं सहायता प्रदान करने हेतु सदैव सजग, संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है।

विश्व संगीत दिवस पर कला-साधना और सांस्कृतिक सौंदर्य से सराबोर रही सांझ

भोपाल। विश्व संगीत दिवस के पावन अवसर पर समूचा मध्य प्रदेश नाद-ब्रह्म की अलौकिक स्वर-लहरियों से गुंजायमान हो उठा। संस्कृति विभाग के तत्वावधान में प्रदेश के 14 अंचलों में कला-साधना और सांस्कृतिक सौंदर्य का एक ऐसा अनुपम वितान तना, जिसने युवा पीढ़ी में नई सांस्कृतिक चेतना का संचार कर दिया। शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों सहित विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों में आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं से जोड़ना एवं उनमें सांस्कृतिक चेतना का संवर्धन करना रहा। इसी श्रृंखला में, मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित 'संगीत संध्या' मुख्य आकर्षण रही, जहाँ कला-साधना और सांस्कृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिला। इस शाम पुणे की सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना सुश्री स्मिता महाजन की लयात्मक प्रस्तुतियों और भोपाल की गुणी गायिका सुश्री प्रदक्षिणा भट्ट के मनोहारी शास्त्रीय गायन ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन में एक सराहनीय प्रयास सिद्ध हुआ। इस अवसर पर संचालक, संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव एवं संस्कृति संचालनालय की उप संचालक डॉ. पूजा शुक्ला ने उपस्थित कलाकारों का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

राष्ट्रपति ने किया चीता कमांड कंट्रोल सेंटर का भ्रमण, चीता प्रदर्शिनी भी देखी

भोपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कूनो नेशनल उद्यान के दो दिवसीय प्रवास के दौरान रविवार को चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। चीता कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को चीतों कि निगरानी और ट्रैकिंग की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी।

राष्ट्रपति ने चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर परिसर में चीता प्रोजेक्ट की अभी तक की प्रगति पर लगाई गई प्रदर्शिनी का अवलोकन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को अवगत कराया गया कि वर्तमान में भारत में चीतों की संख्या 52 है, जिनमें से 49 चीते कूनो में मौजूद है, तीन चीते गाँधी सागर अभयारण्य मंदसौर भेजे गए है।

राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा इस दौरान चीतों के लिए की गई आवश्यक सुविधाओं के विषय में जानकारी ली गई। बताया गया कि हर 2 किलोमीटर पर जंगल में वाटर पिट बनाये गए हैँ जिनमें अवश्यकता अनुसार पानी भरवाया जाता है। इस दौरान उन्हें बोत्सवाना से लाये गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गयी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति श्री मुर्मु द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किये गए थे जिन्हें कुनो लाया गया है।

इस दौरान सीसीफ श्री उत्तम कुमार, कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा, डीएफओ श्री आर थिरूकुराल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु अपने दो दिवसीय प्रवास पर रविवार को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क पहुंचीं। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल भी साथ रहे।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 हजार से अधिक श्रमिकों ने किया सामूहिक योगाभ्यास

मंत्री श्री पटेल के आह्वान पर श्रमिकों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का लिया संकल्प

भोपाल। श्रम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें योग से जुड़ने का विशेष आह्वान किया था। मंत्री श्री पटेल के इस प्रेरक आह्वान का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला! अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के औद्योगिक और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में श्रमिकों ने बढ़-चढ़कर योगाभ्यास किया। प्रदेश के कुल 337 संस्थानों में 15 हजार से अधिक श्रमिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया।

सचिव श्रम श्री रघुराज राजेंद्रन ने कहा कि योग किसी एक दिवस तक सीमित न होकर, श्रमिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि श्रमिक प्रतिदिन योग से जुड़ें, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रह सकें। एक स्वस्थ और ऊर्जावान श्रमिक ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

श्रम विभाग और मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल के प्रयासों से आयोजित इस प्रदेश स्तरीय योग कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। श्रम मंत्री श्री पटेल ने स्वयं जबलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्रमिकों के साथ योग किया। इसी क्रम में, श्रम आयुक्त श्री संदीप जी आर ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स स्कूल में आयोजित मंडल के विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से प्राप्त तस्वीरों और जानकारियों के अनुसार, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर श्रमिकों का उत्साहवर्धन किया।

संपादक: अली आदिल खान द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती बाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।